● वर्ष-5

● अंक-245

रायपुर, शनिवार
30 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8› जनजातीय समुदाय के समग्र विकास ...

एनटीए को लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - यूपीएससी में कभी नहीं हुआ पेपर लीक



नईदिल्ली। नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित करती हैं।जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, यूपीएससी की परीक्षाओं में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। एनटीए को उससे सीखने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समाधान तभी संभव है जब यह स्पष्ट हो कि किसी विफलता की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है। केवल संस्थागत जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि एनटीए में 卐संस्थागत निरंतरता卐 विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में एजेंसी के पास परीक्षाएं निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने की क्षमता और विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

सुनवाई के दौरान 2024 में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि समिति ने 35 दीर्घकालिक और लगभग 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थीं, जिनमें से अधिकांश को लागू किया जा चुका है। हालांकि अदालत ने पूछा कि यदि सुधार लागू किए गए थे, तो फिर इस वर्ष पेपर लीक जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: मोदी



देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (नीट) में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को कड़ी फटकार लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है और लाखों छात्रों व उनके परिवारों के लिए पूरा मामला बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त कर कहा कि छात्र अपनी युवावस्था के सबसे महत्वपूर्ण साल, अपना समय, पैसा और भावनाएं परीक्षा में लगाते हैं। इसके बाद में, यदि हर साल परीक्षा की विश्वसनीयता और शुचिता पर सवाल उठते हैं, तब यह पूरे शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा दाग है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे विवाद पर निगरानी रख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।इस गंभीर स्थिति के बीच, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को भंग करने या उसके पूरे ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और विश्वसनीय संस्था के गठन की वकालत की, ताकि छात्रों का खोया हुआ विश्वास बहाल हो सके। मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एनटीए और पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन से सीधे सवाल पूछा कि आखिर बार-बार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं।

आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में दावा

देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट और इसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देश के आर्थिक विकास और महंगाई के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं, हालांकि विकास की संभावनाएं अब भी सकारात्मक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मजबूत बने रहने की उम्मीद है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का लगातार जारी रहना निकट भविष्य में कॉर्पोरेट की आय और बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

इसमें पश्चिम एशिया संकट और उसके कारण ईंधनों की कीमतों में तेजी, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, वैश्विक व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता तथा मौसम संबंधी चिंताओं के कारण विकास और महंगाई दर पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका व्यक्त की गयी है।

4 वजहों से बरकरार रहेगी भारत की मजबूत ग्रोथ

- कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकों की बैलेंस शीट बेहद मजबूत स्थिति में हैं।
- सरकार की तरफ से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है।
- देश के पास पर्याप्त मात्रा में फूड स्टॉक मौजूद है।
- खेती-किसानी का उत्पादन स्थिर बना हुआ है।



केंद्रीय बैंक ने कॉर्पोरेट और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर और प्रमुख साझेदार देशों के साथ व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन से निवेश और विकास की गति बनी रहने की उम्मीद जतायी है।

रिपोर्ट में कहा गया है, कुल मिलाकर, मजबूत बुनियादी आर्थिक स्थिति और मजबूत बैलेंस शीट के चलते घरेलू वित्तीय प्रणाली प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है।

इसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि सरकार की राजकोषीय संतुलन बनाये रखने की प्रतिबद्धता और रिजर्व बैंक द्वारा तरलता बढ़ाने के उपाय बॉन्ड यील्ड पर दबाव को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल, उर्वरक और सोने की ऊंची कीमतों से विदेशी मुद्रा व्यय पर दबाव बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक और सोने की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि का भी सामना कर रहा है। इन तीनों के भुगतान विदेशी मुद्रा में करने होंगे। वहां रुपये में व्यापार नहीं हो रहा है।



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने की। (विस्तृत समाचार पेज-8 पर)

भाग रहे घुसपैठिये बता रहे टीएमसी का सच!

लोगों के पास मिला आधार, राशन और पैन कार्ड



नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर सीमा क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें उस गंभीर समस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिस पर वर्षों से बहस होती रही है। सीमा के निकट सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक अपने सामान और परिवार के साथ वापस लौटने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही पहचान जांच, पंजीकरण और निरोध केंद्रों की व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध घुसपैठ के विरुद्ध अब कठोर कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों का विवरण तैयार किया जा चुका है। इनमें से अनेक लोगों ने स्वयं स्वीकार किया कि वह वर्षों पहले दलालों और बिचौलियों की मदद से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। कोई रोजगार की तलाश में आया, कोई बचपन में परिवार के साथ सीमा पार कर लाया गया। कई लोगों ने यह भी माना कि हाल के महीनों में दस्तावेजों की जांच, पुलिस की सक्रियता और कानूनी कार्रवाई के भय ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनेक लोगों के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी पाये जा रहे हैं। कुछ ने तो वर्षों तक चुनाव में मतदान करने की बात भी कही है। यह स्थिति उन गंभीर सवालों को जन्म देती है जिनका उत्तर प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को देना होगा। यदि अवैध रूप से आए लोग वर्षों तक विभिन्न दस्तावेज प्राप्त करते रहे, तो यह व्यवस्था की खामियों का भी विषय है। लौट रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खुले तौर पर यह भी बताया कि किस प्रकार दलालों के संगठित गिरोह रात के अंधेरे में सीमा सुरक्षा बल की गश्त पर नजर रखते थे और जैसे ही निगरानी में थोड़ी सी ढील दिखाई देती थी, घुसपैठियों को भारत में दाखिल करा दिया जाता था। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि महज दस मिनट के भीतर सीमा पार कराई जा सकती थी। इन बयानों से स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित और संगठित तंत्र सक्रिय था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी की। देखा जाये तो मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस स्पष्टता के साथ अपनी नीति रखी है, वह हर बंगालवासी को भा रही है इसलिए लोग सरकार की काफी सराहना कर रहे हैं।

प्रमुख समाचार

विनम्रता और क्षमाशीलता ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण: मोदी



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक साझा किया और जीवन मूल्यों पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विनम्रता, क्षमाशीलता और उत्तम आचरण ही किसी व्यक्ति के वास्तविक आभूषण होते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि इन्हीं गुणों के साथ देश के नागरिक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। को साझा किया और इसका गहन अर्थ भी समझाया। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि तेजस्विता, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्र आचरण, अहंकार रहित व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति निष्ठा जैसे गुण किसी श्रेष्ठ और दैवी संपदा वाले व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषित और श्लोक साझा कर रहे हैं।

इस्राइल को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला



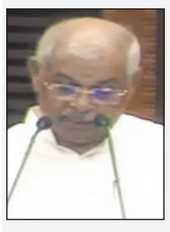
नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस्राइल के प्रति कथित रूप से एकतरफा समर्थन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति और मानवीय मूल्यों के विपरीत है व यह करोड़ों भारतीयों के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह विवाद उस समय सामने आया जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक कथित बयान का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि नेतन्याहू ने एक सम्मेलन में दावा किया कि दुनिया के अधिकांश देशों में इस्राइल की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व की लक्षित हत्या की कभी निंदा नहीं की।

एआईएडीएमके के 90% लीडर्स पाला बदल लेंगे : टीवीके मंत्री



चेन्नई। तमिलनाडु के मंत्री आदव अर्जुन ने कहा कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एआईएडीएमके) के भीतर दरार आने वाले समय में और गहरी होने की संभावना है और अगले एक महीने में इसके 90 प्रतिशत नेता मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) में शामिल हो जाएंगे। चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, तमिलनाडु के मंत्री ने 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एआईएडीएमके में शामिल हुए विधायकों के बारे में भी बात की और कहा कि टीवीके में सभी का स्वागत है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को अपना आधार बढ़ाने के लिए हर हफ्ते सदस्यता अभियान चलाना चाहिए। मीडिया के अनुसार, विल्लीवाक्कम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अर्जुन ने कहा, हम यहां आने वाले हर व्यक्ति का स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं, जैसे वे एक ही परिवार के सदस्य हों। एक महीने के भीतर, एआईएडीएमके के 90 प्रतिशत सदस्यों के टीवीके में शामिल होने की उम्मीद है।

केरल विधानसभा में वंदे मातरम पर विवाद



तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शुक्रवार को संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के नीतिगत भाषण के दौरान राज्य विधानसभा में वंदे मातरम का पूर्ण गायन न होने पर नाराजगी व्यक्त की। विधानसभा से लौटने के बाद लोकसभा में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल की उपस्थिति में आधिकारिक समारोहों में उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। केरल विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के नीतिगत भाषण से पहले और बाद में, एक बैंड टीम ने वंदे मातरम के शुरुआती श्लोक प्रस्तुत किए। वंदे मातरम का पूर्ण गायन अनिवार्य है। राज्यपाल ने कहा कि जब भी राज्यपाल सदन में उपस्थित हों, वंदे मातरम का पूर्ण गायन अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गीत केवल बजाया गया, गाया नहीं गया। जब भी राज्यपाल उपस्थित हों, इसे पूर्ण रूप से गाया जाना चाहिए। इसे गाया नहीं गया; केवल बजाया गया।

कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज : एचके पाटिल



बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है और अब संगठन में एकता बनी हुई है। मीडिया से बातचीत में पाटिल ने स्पष्ट किया कि यह बैठक 30 मई को शाम 4 बजे तय की गई है और उन्हें विश्वास है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे किसी पद (जैसे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मंत्री या उपमुख्यमंत्री) के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी पद की इच्छा नहीं रखते और पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, वे उसे निभाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं और संगठन के निर्णयों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर सभी मतभेद सुलझ चुके हैं और किसी भी नेता में असंतोष की स्थिति नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की सफल यात्रा

मृत्युंजय दीक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की छह दिवसीय यात्रा संपन्न हो चुकी है। पश्चिमी एशिया संकट सहित दुनियाभर में चल रही उथल -पुथल तथा चीन की विस्तारवादी नीतियों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इन देशों से द्विपक्षीय संबंध सुधारने की दिशा में एक अहम पड़ाव बनी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान उन्हें स्वीडन तथा नार्वे जैसे देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सम्मानित किया। नार्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-नार्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के दौरान कुल 57 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ हैं। इन यात्राओं का एक परोक्ष संदेश यह भी है अब भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कूटनीति की छत्रछाया से बाहर निकल कर अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है।

यूएई की यात्रा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के प्रथम चरण में यूएई पहुंचे। यहाँ भारत और यूएई के मध्य सात समझौते हुए। इन समझौतों के अंतर्गत भारत व यूएई में संयुक्त तौर पर पेट्रो उत्पादों के रणनीतिक भंडार बनाए जाएंगे। यूएई भारत में दीर्घकालिक तौर पर एलपीजी आपूर्ति करेगा, पांच अरब डॉलर का नया निवेश करके भारत में सुपर कंप्यूटर क्लस्टर स्थापित करेगा। एक समझौता गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर बनाने



को लेकर भी है। इससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोनो देशों की कंपनियां मिलकर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करेंगी जो एआई ट्रेनिंग, रिसर्च और बड़े-बड़े मॉडल चालने के लिए प्रयोग की जाएगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, औद्योगिक सहयोग, नवाचार उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास शिक्षा एवं सैन्य डॉक्ट्रिन, विशेष अभियान, अंतर-संचालन क्षमता, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सुरक्षित संचार और सूचना आदान प्रदान के लिए एक व्यापक रणनीतिक ढांचा स्थापित करने की सहमति बनी है।

नीदरलैंड- अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे जहां उनका भव्य व गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारत और नीदरलैंड के मध्य 17 द्विपक्षीय समझौतों से एक नया रिकॉर्ड बना। भारत और नीदरलैंड व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जे टेन के मध्य हुई वार्ता के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में 17 समझौते हुए। हरित हाइड्रोजन के विकास पर सहमति के साथ दोनों देश संयुक्त रक्षा उपकरण प्रणाली घटकों और अन्य प्रमुख क्षमताओं के संयुक्त निर्माण के लिए रक्षा औद्योगिक रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उद्यमों की स्थापना शामिल है। संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने विज्ञान और नवाचार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, समुद्री विकास और जन संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। आव्रजन मोबिलिटी पर भी समझौता हुआ। इसके अंतर्गत कुशल भारतीय पेशवेरों के लिए नीदरलैंड में काम करने की प्रक्रियाओं को आसान व निष्पक्ष बनाया जाएगा। अवैध प्रवासन रोकने के लिए भी सहमति बनी है। नीदरलैंड के पास पानी के प्रबंधन की बेहतरीन तकनीक है जिसमें भारत के साथ सहयोग मजबूत होगा। समझौतों से अर्धचालक, अहम खनिज, स्वास्थ्य, जल, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि व संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। इस दौरे की एक बड़ी बात यह रही कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेटेन ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगात आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन का भरोसा दिया।

स्वीडन- प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अपनी यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन पहुंचे जहां एयरपोर्ट पर स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

भारी मात्रा में बरामद किया नक्सली डंप



जगदलपुर। जगदलपुर में कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गट्टाकाल-गोमे के जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत अहम सफलता मिली है। आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., डीआईजी बीएसएफ दीपक तिवारी, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा एवं 40वीं वाहिनी बीएसएफ के सेनानी रणधीर सिंह गिल के निर्देश में चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस, डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस टीम ने सघन सर्चिंग करते हुए नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डम्प बरामद किया।सुरक्षा बलों ने बीडीएस टीम की सावधानीपूर्वक जांच के बाद डम्प को खोला गया। जहां से 29 लाल कपड़े के पैकेट बरामद हुए, जिनकी कुल लंबाई लगभग 580 मीटर बताई गई है। इसके अलावा काले रंग के ढीले कपड़े के दो टुकड़े भी जब्त किए गए। बरामद सामग्री को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित कब्जे में लेकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।कांकेर पुलिस के अनुसार नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सर्चिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बस्तर में बिना लैब कैसे होगी जहरीले फलों की पहचान

देखकर जांच के दावों पर उठे सवाल



जगदलपुर। बस्तर में लोगों की थाली तक पहुंच रहे फल और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भले ही सड़े-गले फलों पर कार्रवाई का दावा कर रहा हो, लेकिन सबसे गंभीर सवाल केमिकल जांच को लेकर सामने आया है। विभागीय अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि फिलहाल बस्तर में फलों और सब्जियों की स्थानीय स्तर पर लैब टेस्टिंग की सुविधा मौजूद नहीं है। यानी जिन फलों को आम जनता खरीदकर खा रही है, उनमें कैल्शियम कार्बाइड, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या दूसरे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी तत्काल वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पा रही। अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि फलों को किस प्रकार के रसायनों से पकाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आंखों से देखकर कैसे तय होगा कि फल जहरीले केमिकल से पकाए गए हैं या नहीं? हालांकि विभाग कुछ संदिग्ध फलों और सब्जियों के सैंपल लेकर उन्हें रायपुर स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेजता है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बस्तर संभाग में खुद की कोई अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब नहीं होने की वजह से जांच प्रक्रिया पूरी तरह बाहरी लैब पर निर्भर है।

ऐसे मामलों की वैज्ञानिक जांच स्टेट फूड टेस्टिंग लैब, हब्बर मान्यता प्राप्त लैब या स्वस्थ्य अफ्रूव्ड लैब में होती है, जहां केमिकल एनालिसिस के जरिए प्रतिबंधित पदार्थों की पुष्टि की जाती है। फिलहाल बस्तर में विभाग ने 62 किलो सड़े-गले फल नष्ट करने की बात कही है, लेकिन केमिकल से पकाए गए फलों पर कोई स्थानीय लैब रिपोर्ट सामने नहीं आई है। यानी बस्तर में खाद्य सुरक्षा का बड़ा हिस्सा अभी भी संदेह और दिखने के आधार पर चल रहा है, जबकि लोगों की सेहत वैज्ञानिक जांच और पुख्ता प्रमाण की मांग कर रही है।

तेंदूपत्ता अग्निकांडः डीएफओ को हटाने के बाद उठे सवाल

- बाकी दोषियों पर कब होगी कार्रवाई? लघु वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष बोले दोषियों को नहीं छोड़ेंगे



बीजापुर। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम ईटपाल स्थित तेंदूपता गोदाम में आग लगने से लगभग 25 हजार मानक बोरा यानि 8-10 करोड़ का तेंदूपत्ता जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। इससे सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने बीजापुर वनमंडलाधिकारी रमेश जांगड़े को हटा दिया है। वहीं मामले की जांच कर बाकी दोषियों पर भी जल्द कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस मामले में डीएफओ को हटाने के बाद अन्य लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई में देरी से कई सवाल उठ रहे। जिस वक्त आग की चिंगारी तेंदूपतों में लगी उस वक्त पर विभाग के जिम्मेदार अफसर कहां थे? चूंकि उठाई-दुलाई का कार्य उक्त स्थान पर चल रहा था। गोदाम में तेंदूपतों बोरों को रखने की तैयारी से पहले विभाग द्वारा आग बुझाने के उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था आखरी क्यों नहीं की गई? शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लघुवनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष रूपसाय सलाम अचानक बीजापुर पहुंचे और ईटपाल तेंदूपत्ता गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान सलाम ने कहा, इस मामले पर विभागीय व पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। डीएफओ पर कार्रवाई किस प्रकार से हुई है, इसका अंदाजा हमें तो नहीं है पर इसमें जो कोई भी हो चाहे निचले स्तर के अधिकारी हो या बाहरी हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई अवश्य होगी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार घटना में संलिप्त निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी अपनी साख व नौकरी बचाने के उद्देश्य से अब सरकार के छुटभैय्या नेताओं के घरों व सर्किट हाउस का दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। क्या तेंदूपत्ता अग्निकांड मामले में सरकार के मंत्री द्वारा कार्रवाई के बाद क्या मामले में संलिप्त अन्य निचले अधिकारियों व कर्मचारियों पर आगे कार्रवाई होगी या यह मामला केवल यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा?

कलेक्टर ने महानदी उद्गम क्षेत्र से सोंढूर नहर तक निरीक्षण अभियान चलाया



धमतरी। जिले के नगरी विकासखंड के व्यापक दौरे पर पहुंचे कलेक्टर अबिनाश मिश्रा पूरे समय एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने विभिन्न विकास और जनहितकारी कार्यों का स्थल निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता, प्रगति और जनसुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं और आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। कलेक्टर ने ग्राम फरसिया में आजीविका डबरी और ग्राम गोरेगांव में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन आजीविका शेड का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित पानी टंकी के हैंडओवर में देरी की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रवास के दौरान कलेक्टर ने मेघा फाउंडेशन महानदी पर समतरा, छिपली और नगरी क्षेत्र में बनाए जा रहे चेक डैम कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन के लिए ये संरचनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना चाहिए। बेलरगांव में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने सड़क, गार्डन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, बाउंड्री वॉल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा नोटरी सुविधा नहीं होने की समस्या बताने पर उन्होंने तहसील कार्यालय में जल्द नोटरी सुविधा शुरू कराने और अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही कॉलेज, आईटीआई, सहकारी बैंक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आरक्षित रखने की बात कही। गणेश घाट में सड़क चौड़ीकरण और एनीकट निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था, मलबा निष्पादन और निर्माण गुणवत्ता की जानकारी ली। वहीं नगरी में निर्माणाधीन चौपाटी का निरीक्षण करते हुए पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और आमजन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि यह स्थल भविष्य में पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बन सके। नगरी क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित सोंढूर नहर लाइनिंग परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। कलेक्टर ने फारसिया के पास सिंगपुर-दुगली नहर लाइनिंग कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता और तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर लगभग 4426 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना के लिए 173 करोड़ 28 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रस्तावित है। कलेक्टर ने कहा कि नहर लाइनिंग से जल रिसाव कम होगा और अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने ग्राम फारसिया स्थित महामाया मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर परिसर में सोलर लाइट, पार्क, बैठने की व्यवस्था और पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

6 लाख से ज्यादा के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार



बालोद। छत्तीसगढ़ की बालोद पुलिस का गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है, जो पावर एक्सल गाड़ी से गांजा की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। यह पूरा मामला पुरुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, पुरुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने टीवीएस एक्सेल 100 क्रमांक सीजी 24 च 0170 से मादक पदार्थ गांजा ले जा रहा है।

सूचना के बाद पुरुर थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और उनकी टीम ने मूरपार के पास गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद जब उसकी तलाशी ली गई, तो 6 लाख 5 हजार रुपए का 12।100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रवि नेताम पिता नरेश नेताम उम्र 40 वर्ष बताया, जो कि कसेरी गांव में मनेरीपारा का रहने वाला है। उसने बताया कि वह गांजा को बालोद से रायपुर ले जा रहा था।

पुलिस ने उसके पास से 12।100 किलोग्राम गांजा और प्रयुक्त गाड़ी को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 20 (क्र) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

अमानक खाद पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन



बिलासपुर। अमानक खाद पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतनपुर की दुकानों से 180 क्विंटल अमानक खाद जब्त किया है।

साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई, जिससे बाकी दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने बिलासपुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया।

कृषि विभाग की टीम ने रतनपुर क्षेत्र की कई दुकानों और समितियों की जांच की। सेवा सहकारी समिति चपोरा में रिकॉर्ड और भंडारण में अनियमितताएं पाई गई।

मेंसर्स गुप्ता ग्रेन मर्चेंट रतनपुर में भी गड़बड़ियां उजागर हुई। सेवा सहकारी समिति रतनपुर में अभिलेखों में खामियां पाई गई। उन्नत कृषि सेवा केंद्र रतनपुर में भी नियमों का उल्लंघन सामने आया। यहां खाद विक्रय और भंडारण संबंधी कई अनियमितताएं मिलने से कृषि विभाग ने संबंधित संस्थाओं और विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है ।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुलिस के हत्थे चढ़े दो गांजा तस्कर बाइक से कर रहे थे तस्करी

बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में पुलिस की ओर से सघन जांच अभियान के तहत असामाजिक तत्वों, अवैध महुआ शराब बनाने वाले, जुआ-सट्टा और गांजा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने दो तस्करों लखन वर्मा और मुकेश कुमार को पकड़ा है, जो बाइक से गांजा तस्करी कर रहे थे। तस्करों के पास से एक लाख रुपए का गांजा, दो मोबाइल और बाइक जब्त किया गया है। यह मामला लवन थाना क्षेत्र का है। दरअसल, जांच में जुटी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बाइक सवार गांजा रखकर जा रहे हैं। सूचना पर एक्शन लेते हुए घेराबंदी की गई और पल्सर बाइक पर सवार दो आरोपियों को रोका गया। वहीं जब टीम ने उनके पास मौजूद पिट्ठू बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर से 10.204 किलो गांजा बरामद किया गया।जब्त गांजा की कीमत एक लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही पुलिस की टीम ने घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइक और दो मोबाइल भी जब्त किया। दोनों आरोपियों ने अपना नाम लखन वर्मा और मुकेश कुमार बताया।

जीपीएम में ज्वेलर्स प्रदीप सोनी की हत्या से लोगों में आक्रोश

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कोटमी साप्ताहिक बाजार में ज्वेलर्स संचालक प्रदीप सोनी की लूट और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जिले में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नाराज परिजन, व्यापारी संघ और स्थानीय नागरिकों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस मार्च में काफी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से मार्च निकाला। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आरोपियों तक न पहुंच पाना चिंता का विषय है। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

भिलाई में पानी-बिजली का संकट, कांग्रेस पार्षदों ने दिया धरना

दुर्ग। जिले में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच भिलाई शहर में पानी और बिजली का संकट गहरा गया है। आम जनता को हो रही भारी परेशानी को लेकर भिलाई नगर निगम के सामने खुद सत्तापक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जनता हमें उम्मीद से पार्षद बनाती, हम भी चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी कर सकें। शहर सरकार हमारी है लेकिन नगर निगम के अधिकारी शासन के अधीन हैं, उनकी लापरवाही से कोई काम नहीं हो रहा है, आयुक्त को हटाने की भी हम मांग रख चुके हैं- लालचंद वर्मा, पार्षद प्रदर्शनकारी पार्षदों ने निगम प्रशासन पर जनता की मूलभूत समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन होने का गंभीर आरोप लगाया है। धरने की कमान संभाल रहे विद्युत यांत्रिकी विभाग के एमआईसी सदस्य और पार्षद लालचंद वर्मा ने कहा कि शहर के कई इलाकों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दूर-दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के कारण बोर सूख चुके हैं।

झुमका बोट क्लब में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप

कोरिया। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका बोट क्लब में पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गुरुवार शाम स्थानीय लोगों और बोट क्लब के संचालक व गार्ड के बीच पार्किंग व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान बोट क्लब परिसर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पार्किंग को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ने पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और फिर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति कुछ देर तक तनावपूर्ण बनी रही। विवाद का पूरा घटनाक्रम बोट क्लब परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। सामने आए फुटेज में साफ तौर पर लोगों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट होती दिखाई दे रही है।घटना की सूचना मिलते ही मामला बैकुंठपुर थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

एचसी में नौकरी के लिए फर्जी सर्कुलर पेश, याचिका रद्द

बिलासपुर। संविदा नियुक्त एक महिला आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका मामले में हाईकोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया है। दरअसल, मामले में याचिकाकर्ता महिला डॉक्टर ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष एक सर्कुलर पेश किया। बाद में पता चला कि सर्कुलर पूरी तरह फर्जी था। महिला डॉक्टर को अपनी गलती का अहसास हुआ और कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन दायर करते हुए कोर्ट से माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए उसे दोबारा बहाल किया। बता दें, कि बलौदाबाजार-भाटापारा के मोपका प्राथमिक स्वास्थ्य आयुष केंद्र में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ ममता मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने 28 मई 2010 को जारी सरकारी सर्कुलर पेश किया, इसमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश दिए गए थे। याचिका में सेवाकाल के 18 साल पूरा करने की बात कही गई।

कांग्रेस ने सहकारी समिति का घेराव किया



गरियाबंद। फिंगेश्वर में खाद-बीज की कमी, बिजली कटौती, पेंशन और आवास योजना सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता व किसान सहकारी समिति का घेराव करने के साथ चक्काजाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महिला कांग्रेस और नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं।

कांग्रेस प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के साथ-साथ बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने और गरियाबंद जिले में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि गरीबों और किसानों का हक छीना जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चमगादड़ों की मौतों के बाद जागा प्रशासन

कराया मौके पर पानी का छिड़काव



बलरामपुर। वाड्रफनगर में भीषण गर्मी की वजह से हो रही चमगादड़ों की मौत के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। हालात को देखते हुए पेड़ों पर पानी का छिड़काव कराया गया, जिससे चमगादड़ों को राहत मिल सके। पुलिस चौकी के पास पेड़ों पर रहने वाले हजारों चमगादड़ों की लगातार मौत की खबर सामने आने के बाद वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति का मुआयना करने के बाद पानी के छिड़काव किया गया। वहीं मृत चमगादड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सके। इसके साथ ही इलाके में मृत चमगादड़ों की वजह से फैल रही दुर्गंध के कारण लोगों को हो रही परेशान को ध्यान में रखते हुए निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। चमगादड़ों की मौत के संबंध में पशु चिकित्सक कमला आयाम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि तापमान वर्तमान 40-41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। चमगादड़ों के लिए 39 डिग्री सेल्सियस टिपिंग पॉइंट होता है, जिसके ऊपर तापमान के जाने के बाद चमगादड़ों की 'थर्मो-नेगेटिव' (Heterothermic) सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वे गिरने लगते हैं। हाइपर थर्मिया की वजह से चमगादड़ों के अंग काम करना बंद कर देते हैं, और उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल, मौत के सही कारणों का पता लगाने चमगादड़ों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

नपा में हंगामा: भाजपा-कांग्रेस पार्षदों ने जड़ा ताला

निर्दलीय अध्यक्ष दीप्ती रोहित सारथीके खिलाफ खोला मोर्चा



जांजगीर-चांपा। अकलतरा नगर पालिका में एक बार फिर अध्यक्ष और पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। पार्षदों ने कल सुबह नगर पालिका कार्यलय में ताला जड़कर निर्दलीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले सामान्य सभा की हुई बैठक में अध्यक्ष दीप्ती रोहित सारथी और पार्षदों के बीच बहसबाजी देखने को मिली थी। बताया जा रहा है कि तालाब गहरी करण और प्लेसमेन्ट कर्मचारियों के मामले में विवाद हुआ था। इस दौरान अध्यक्ष बैठक छोड़कर चली गई थी। सामान्य सभा की आज दोबारा बैठक बुलाई गई थी, जिससे आक्रोशित पार्षदों ने भीषण गर्मी के बीच दफ्तर में ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षद शामिल है। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल रमेन डेका से पर्वतारोही सुश्री अंकिता गुप्ता ने की सौजन्य भेंट



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से शुक्रवार को लोकभवन में पर्वतारोही सुश्री अंकिता गुप्ता ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने अपनी पर्वतारोहण उपलब्धियों तथा आगामी अभियानों की जानकारी राज्यपाल को दी। सुश्री अंकिता गुप्ता वर्तमान में कबीरधाम (कवर्धा) पुलिस लाइन में आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में लद्दाख स्थित यूटी कांगड़ी पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। भेंट के दौरान सुश्री अंकिता ने राज्यपाल को बताया कि उनकी अगली योजना अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो पर आरोहण करने की है। उन्होंने अपने अब तक के पर्वतारोहण अभियानों, अनुभवों और भविष्य की तैयारियों से भी राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल रमेन डेका ने अंकिता गुप्ता के साहस, दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि युवा प्रतिभाओं की ऐसी सफलताएं समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने अंकिता को उनके आगामी अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं तथा उन्हें हरसंभव सहयोग देने की बात कही।

बस्तर में चिकित्सा की अलख जगाने वाले पद्मश्री डॉ. गोडबोले दंपति का वित्त मंत्री ने किया आत्मीय अभिनंदन



रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुदूर व वनांचल क्षेत्रों में दशकों से नि:स्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले का पद्मश्री सम्मान से अलंकृत होने पर भव्य स्वागत किया गया। राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को रायपुर स्थित अपने निवास पर गोडबोले दंपति का आत्मीय अभिनंदन किया और उन्हें इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं। इस गरिमामयी मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने गोडबोले दंपति के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले ने बस्तर के अत्यंत दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य सुधार, कुपोषण उन्मूलन और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनका यह समर्पण और सेवा भाव आज के पूरे समाज के लिए एक महान प्रेरणास्रोत है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बस्तर के जिन सुदूर अंचलों में वर्षों पहले बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, वहां इस दंपति ने उम्मीद, उपचार और निश्छल मानवता की अनूठी मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया यह पद्मश्री सम्मान, गोडबोले दंपति के दशकों लंबे कड़े संघर्ष, त्याग और निस्वार्थ लोक-सेवा का एक सच्चा राष्ट्रीय सम्मान है। अभिनंदन समारोह के दौरान बस्तर में स्वास्थ्य क्रांति और सेवा से जुड़े उनके संस्मरणों पर भी चर्चा की गई।

प्राकृतिक आपदा के 2 प्रकरणों में 4-4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 2 प्रकरणों में जशपुर कलेक्टर द्वारा कुल 8 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अपर कलेक्टर प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील तपकरा के ग्राम बांसाझाल निवासी जेवियर बड़ा की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र विक्रम बड़ा को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार तहसील कांसाबेल अंतर्गत ग्राम पोंगरो निवासी लक्ष्मणी पैंकरा की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाने पर उनके पति दिलेश्वर साय को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।

दुर्ग -एर्नाकुलम के मध्य समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा आज से



रायपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग-एर्नाकुलम के मध्य एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। यह गाड़ी विभिन्न श्रेणी के 20 आईसीएफ कोच के साथ चलेगी। गाड़ी संख्या 08707 दुर्ग-एर्नाकुलम समर स्पेशल ट्रेन 30 मई 2026 को दुर्ग स्टेशन से 00.15 बजे रवाना होकर 3:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी यह गाड़ी बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाडा एवं अन्य मध्यवर्ती स्टेशन पर होते हुए 31 मई 2026 को एर्नाकुलम जंक्शन पर 14.00 बजे पहुंचेगी।

किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : रामविचार नेताम

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए कृषि मंत्री, धान की अपेक्षा फसल विविधीकरण और डिजिटल खेती पर दे रहें हैं जोर



रायपुर। धान के कटोरे के रूप में विख्यात छत्तीसगढ़ अब परंपरागत धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और पर्यावरण अनुकूल स्थायी कृषि के एक नए युग में अग्रसर हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए ''नवा अंजोर विज़न 2047'' के तहत किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए चौतरफा रणनीति पर काम शुरू हो गया है। केन्द्रीय कृषि विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी दी।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने सम्मेलन में राज्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का कृषि ढांचा अब एक बड़े बदलाव की ओर है। हमारी सरकार ''नवा अंजोर विज़न 2047'' के जरिए राज्य के लगभग 40 लाख किसान परिवारों, जिनमें 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत जिसमें 31 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल हैं, के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन में वर्ष 2025-26 के दौरान दर्ज की गई 76 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि और तिलहन के रकबे में 28 हजार हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि हमारा किसान अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वहीं खरीफ 2026 में हम अरहर, उड़द और मूंग के लिए क्लस्टर आधारित रणनीति लागू कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य हर हाथ को काम और हर खेत को सही समय पर गुणवत्तायुक्त बीज और संतुलित खाद उपलब्ध कराना है।

राज्य में योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और रणनीतिक तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि कृषि तकनीक, बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक प्रबंधन से खेती की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने सम्मेलन में कहा कि खरीफ 2026 के लिए हमारी तैयारियां पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीक-आधारित हैं। राज्य के किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों की वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। सीमांत किसानों को जहां एकमुश्त उर्वरक दिया जा रहा है, वहीं यूरिया की कालाबाजारी और अत्यधिक खपत को रोकने के लिए लघु व बड़े किसानों को 20 से 25 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार में यूरिया देने की व्यवस्था की गई है। हम डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी, एसएसपी और एनपीके कॉम्प्लेक्स को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा, एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पूरी खरीद और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया गया है।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने कांफ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ वर्ष 2025-26 में दलहन उत्पादन में रिकॉर्ड 76 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके साथ ही तिलहन मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के तहत सरसों, मूंगफली और सोयाबीन के बीज वितरण से तिलहनी फसलों के क्षेत्र में 28 हजार हेक्टेयर से अधिक का विस्तार हुआ है। वहीं क्लस्टर विकास, बागवानी के क्षेत्र में फल, सब्जी और मसाला फसलों के लिए क्लस्टर आधारित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

टिकाऊ और जलवायु अनुकूल खेती के तहत् 23,050 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जा चुका है, जिसमें 461 क्लस्टर्स और 922 कृषि सखियों की मदद ली जा रही है। सॉइल हेल्थ के तहत् वर्ष 2025-26 में 2.81 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। साथ ही, नई पीढ़ी को कृषि से जोड़ने के लिए राज्य के 126 पीएम श्री स्कूलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (सॉइल टेस्टिंग लैब्स) स्थापित की जा चुकी हैं। स्मार्ट इरिगेशन के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत सूक्ष्म सिंचाई और लागत कम करने के लिए ड्रोन तकनीक व 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम' (फसल .पशुपालन .मत्स्य .केंटकी) को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा योजना के डेटा को इंटीग्रेट करके जून से जुलाई 2026 तक विशेष केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। वहीं पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शत-प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने की तैयारी है।

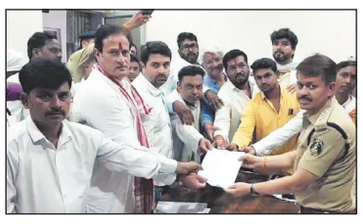
कृषि मंत्री श्री नेताम ने सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मंच के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष कृषि विकास की गति को और तेज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव और अपेक्षाएं भी रखी हैं। इनमें छत्तीसगढ़ धान प्रधान राज्य होने के कारण, फसल विविधीकरण को गति देने के लिए केंद्र से एक पृथक प्रोत्साहन नीति की मांग की गई है। साथ ही प्राकृतिक उत्पादों का एमएसपी प्राकृतिक और जैविक खेती के उत्पादों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था की जाए।

मंत्री श्री नेताम ने सम्मेलन में सप्लाई प्लान और खाद सब्सिडी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता के लिए माहवार सप्लाई प्लान के अनुसार खाद प्रदाय की मांग के साथ ही डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में एनपीके की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को छोटे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया जाए। वहीं उर्वरकों की अत्यधिक खपत और बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार उर्वरकों की 25 किलोग्राम की छोटी बोरी तैयार की जानी अपेक्षित है। साथ ही राज्य के आदिवासी बाहुल्य और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए विशेष कृषि विकास पैकेज तथा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत तकनीकी व आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान की जाए।

इस अवसर पर संचालक कृषि श्री राहुल देव, संचालक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अजय अग्रवाल, संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश चंद्राकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर में मॉल के अवैध रास्ते पर सियासी बवाल

विरोध में उतरे विकास उपाध्याय, अधिकारी के खिलाफ एफआईआर की मांग



रायपुर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसजन शुक्रवार को पंडरी सिटी सेंटर मॉल के लिए एक्सप्रेस-वे के सामने अवैध रूप से मार्ग खोले जाने एवं शासन के नियमों की अवहेलना करने वाले पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने देवेन्द्र नगर थाना पहुंचे।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर स्थित एक्सप्रेस-वे के निर्माण के समय शासन द्वारा स्पष्ट रूप से यह नियम निर्धारित किया गया था कि एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर किसी भी प्रकार का नया मार्ग अथवा कट नहीं खोला जाएगा, ताकि तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं एवं यातायात अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

5 दिसंबर 2017 को जारी शासन के नोटिफिकेशन में भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि एक्सप्रेस-वे से लगी भूमि पर किसी भी प्रकार का नया रास्ता नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों द्वारा नियमों एवं तकनीकी मानकों की अनदेखी करते हुए एक्सप्रेस-वे के सामने अवैध रूप से मार्ग खोल दिया गया है।

उक्त मार्ग खोले जाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि एक्सप्रेस-वे पर वाहन तेज गति से संचालित होते हैं। साथ ही इससे यातायात बाधित होने एवं जाम की स्थिति निर्मित होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और चंद अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा यह खेल अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है।

जानकारी के अनुसार, यह कार्य बिना आवश्यक अनुमति एवं सक्षम विभागों की स्वीकृति के किया गया प्रतीत होता है, जो कि प्रथम दृष्टया शासकीय नियमों का उल्लंघन एवं पद का दुरुपयोग है। इसलिये उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारियों एवं अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने तथा जनहित एवं नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे के सामने खोले गए इस अवैध मार्ग को तत्काल बंद कराये जाने की बात कही। ताकि भविष्य में किसी भी गंभीर दुर्घटना अथवा जनहानि की संभावना को रोका जा सके।

विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार में अधिकारी एक्सप्रेस वे का नियम विपरीत रास्ता खोलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस कार्य में भाजपा मंत्री, नेता, लोक निर्माण विभाग, संबंधित नियोजन अधिकारी, कुछ रसूखदार व्यक्ति, निजी बिल्डर और भू-माफिया भी सिर्फ अपने निजी लाभ के लिये संलिप्त हैं। सिटी सेंटर मॉल के सामने बने एक्सप्रेस-वे का रूट बीच में खोलने वाले अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिये आखिर किसके निजी लाभ के लिए नियमों को शिथिल किया जा रहा है या कौन-कौन व्यक्ति हैं, जिनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस-वे के मूल और तकनीकी रूप से स्वीकृत रास्ते में बदलाव कर रहे है।

विकास उपाध्याय का कहना है कि जहां एक तरफ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए बड़े कॉलोनाइजरों से मिली भगत कर आम जनता को दुर्घटनाओं के लिए आमंत्रित कर रहे है। कांग्रेस पार्टी का सीधा दावा है कि यह कार्य निजी और आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे प्रोजेक्ट की दिशा बदली जा रही है।

ब्राम्हणपारा वार्ड क्षेत्र धोबीपारा उद्यान परिसर के समीप आरआरआर सेंटर नये स्वरूप में प्रारंभ



रायपुर। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025-26 अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन कमांक 4 क्षेत्र के अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्षेत्र अंतर्गत धोबीपारा उद्यान के समीप सामुदायिक भवन में गुरुवार को आरआरआर सेंटर नये स्वरूप में प्रारंभ हो गया। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने इस नये स्वरूप वाले सेंटर का फीता काट उदघाटन किया।

इस नये स्वरूप वाले आरआरआर सेंटर में नगर निगम रायपुर द्वारा एक ई बैटरी वाहन उपलब्ध कराया गया है जो नगर निगम जोन क्रमांक 4 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 7 वार्डो में जाकर वहां से रहवासी नागरिकों के घरों से अनुपयोगी वस्तुएं संग्रह करके लाने का कार्य करेगा, जिन्हें समाज के जरूरतमंद नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन योजना स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025-26 अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

आरआरआर सेंटर में नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर महिलाओं के कल्याणार्थ सिलाई मशीन की व्यवस्था दी गई है। जिस पर महिलाएं कार्य कर रोजगारयुक्त हो सकेंगी एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। यहां नये स्वरूप वाले आरआरआर सेंटर का संचालन धरोहर स्वसहायता समूह की पदाधिकारी महिलाओं के माध्यम से जनहित में योजना अंतर्गत किया जायेगा। साथ ही वहां बर्तन बैंक, झोला बैंक की व्यवस्था रखी गयी है। अलग - अलग आलमारियों के खंड़ों में पुराने कपड़ों , जूते -चप्पलों , इलेक्ट्रॉनिक सामानों, पुराने बर्तनों, पुराने प्लास्टिक सामानों अन्य पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं को रखने की व्यवस्था दी गई है। जिससे नागरिकों को यहां नगर निगम जोन 4 के ब्राम्हणपारा वार्ड क्षेत्र में धोबीपारा उद्यान के समीप सामुदायिक भवन तक पहुंचकर अपने घरों की अनुपयोगी वस्तुओं को देना सहज और सरल हो सके। इससे पर्यावरण संरक्षण सहित जरूरतमंद नागरिकों तक उनके उपयोग की वस्तुएं सहजता से पहुंचायी जा सकेंगी।

महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नागरिकों को बताया कि आरआरआर (रिड्यूज, रियूज, रिसायकल) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य कचरे को स्रोत पर कम करना, उपयोग योग्य वस्तुओं का पुन:उपयोग बढ़ाना तथा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर संसाधनों का संरक्षण करना है। इसके माध्यम से लैंडफिल में जाने वाले कचरे में कमी आती है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और सर्कुलर इकॉनमी को मजबूती मिलती है। आरआरआर सेंटर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

टेम्पू में जनसमस्या निवारण शिविर आज

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। इसी क्रम में 30 मई 2026 को जशपुर जिले के जनपद पंचायत मनोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत टेम्पू में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में 13 गांवों के ग्रामीण शामिल होकर अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। शिविर में सुरजूला, रजला, खुटापानी, घाघरा, करदना, टेम्पू, मुटू, पोड़ीपटकोना, चड़िया, सोगड़ा, मनोरा, खोगा एवं डुमरटोली के ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेगा निजी स्कूलों में दाखिला : सचिव



रायपुर। श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में श्रम विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं श्रम मंत्री श्री लखन देवांगन के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले इस दिशा में विभाागीय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर श्रमायुक्त द्वय श्री एस.एल. जांगड़े एवं श्रीमती सविता मिश्रा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के सचिव श्री गिरीश रामटेके, श्रम विभाग के उप सचिव श्री विपुल गुप्ता सहित विभिन्न जिलों से आए श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिले। इस दिशा में विभागीय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रारंभ होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र से सीटों की संख्या बढ़ाकर 100 से 200 कर दी गई है। इस योजना से निर्माण श्रमिकों के बच्चों के प्रदेश के निजि स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। इनका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। श्रमायुक्त ने जिलों के श्रम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस योजना में अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलता है अथवा किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी जवाबदेह होंगे और उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नियद नेल्लानार 2.0 : बस्तर के सुदूर अंचलों में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

गांव-गांव तक पहुंचेगी शासन की प्रमुख योजनाएं : मुख्य सचिव



रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के माध्यम से माओवादी प्रभावित और सुदूर अंचलों के ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू होने जा रहा है। इस नई कार्ययोजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ (संतृप्तिकरण) सुनिश्चित किया जाएगा।

शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और सुघ्घर छत्तीसगढ़ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि योजना के पहले चरण (1.0) के तहत बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिले के सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में 25 हितग्राही मूलक और 14 सामुदायिक सुविधाएं पहुंचाई गई थीं। अब इसके दूसरे चरण (नियद नेल्ला नार 2.0) का दायरा बढ़ाते हुए 31 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 वांछित सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएंगी।

गांव-गांव पहुंचेंगी ये प्रमुख 31 व्यक्तिगत योजनाएं- इस विशेष अभियान के तहत हर पात्र ग्रामीण का डेटा तैयार कर उन्हें योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा। मनरेगा जॉब कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड और मुफ्त राशन वितरण योजना, आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण, जननी सुरक्षा योजना और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, महिला एवं बाल विकास की प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और महतारी वंदन योजना से जोडा जाएगा। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा के तहत स्कूली बच्चों को नि:शुल्क गणवेश व पाठ्यपुस्तकें और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सभी पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड बनेंगे। श्रम कार्ड, वोटर आईडी, व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र सहित जाति, जन्म, निवास, मृत्यु और ई-डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनेंगे।

14 सामुदायिक सुविधाओं से सुदृढ़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर- सुदूर वनांचलों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए गांवों में ये 14 सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित मूल्य की राशन दुकानें, सड़क व मोबाइल कनेक्टिविटी, डाकघर, वन धन विकास केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र , पंचायत भवन, बैंक और ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

इस सघन संतृप्तिकरण अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए आयोजित इस बैठक में बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के कड़े निर्देश दिए।

क्वाड के वार से तिलमिलाये चीन-पाकिस्तान

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली में हुई क्वॉड देशों की बैठक ने चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। दूसरी तरफ क्वॉड के मंच से चीन की विस्तारवादी चालों पर भी घेरा कस दिया गया। बस फिर क्या था, बौखलाए चीन और पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जहरीला बयान जारी कर अपनी कुंठा बाहर निकालनी शुरू कर दी। लेकिन नए भारत ने भी बिना देर किए ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन और पाकिस्तान के साझा बयान को पूरी तरह अनावश्यक और अस्वीकार्य बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी दूसरे देश की इतनी औकात नहीं कि वह भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करे। नई दिल्ली ने यह भी जता दिया कि भारत अब हर उकसावे का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा के दौरान जारी साझा बयान में चीन ने जम्मू-कश्मीर को तथाकथित इतिहास से जुड़ा विवाद बताने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर वही पुराना राग अलापा और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की आड़ लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने तुरंत उनकी इस साजिश की धज्जियां उड़ा दीं। नई दिल्ली ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर पर भारत की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट और अटल है। दुनिया की कोई ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकती। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भी बेहद कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि इस परियोजना का हिस्सा भारत की उस संप्रभु भूमि से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत ने दो टूक चेतावनी दी कि किसी भी देश को पाकिस्तान के इस गैरकानूनी कब्जे को वैधता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सीधा संदेश चीन के लिए था, जो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ चालें चलता रहता है। साथ ही नई दिल्ली ने चीन और पाकिस्तान के तथाकथित सीमा पार जल सहयोग के दावे की भी हवा निकाल दी। भारत ने तीखा सवाल पूछा कि जब चीन और पाकिस्तान की कोई साझा सीमा ही नहीं है तो फिर यह कथित सीमा पार जल सहयोग आखिर किस आधार पर हो रहा है। यह सवाल चीन की उस चालाक नीति पर जोरदार तमाचा है जिसके जरिये वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर भी जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपनी हताशा जाहिर कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तथाकथित भारतीय कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान आज आर्थिक बर्बादी, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा है। दुनिया उसे आतंक फैलाने वाले देश के रूप में देखती है और अब वह चीन के सहारे भारत के खिलाफ बयानबाजी कर अपने लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन की भूमिका भी पूरी तरह दोहरी और स्वार्थी नजर आई। एक तरफ वह भारत के साथ संबंध सुधारने की बात करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की अखंडता पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को अब यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि यह नया भारत है। अब भारत हर मंच पर आंख में आंख डालकर जवाब देता है और अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करता।

कर्नाटक में शुरू हुई संकटमोचक की अग्नि परीक्षा

अभिनय आकाश

ईद उल अजहा जिसे भारत में आमतौर पर बकरीद के नाम से भी जानते हैं। दुनियाभर के मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन खास नमाज अदा की जाती है और जानवरों की कुर्बानी भी होती है। लेकिन आज बात बकरीद की नहीं बल्कि राजनीति की करेंगे। दरअसल, कर्नाटक की सियासत में एक ऐसा अध्याय लिखा जा चुका है, जहाँ भावुकता और भारी राजनीतिक पैंतरेबाज़ी एक साथ देखने को मिली। डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उनके नाम का प्रस्ताव खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रखा। इस फैसले के आते ही शिवकुमार के आवास के बाहर मानों कोई किला तैयार होने लगा। बैरिकेड्स लग गए और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यह सब कुछ इडली, वड़ा और चौ-चौ बाथ से सजी एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के ठीक बाद हुआ। नाश्ते की मेज से उठते ही माहौल गहरे जज्बात में डूब गया। डीके शिवकुमार की आँखें नम थीं और उन्होंने सिद्धारमैया के पैर छुए और दोनों नेता एक-दूसरे के गले लग गए। संयोग देखिए कि यह सब कुछ बकरीद के आसपास हो रहा है। एक ऐसा त्योहार जो अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी और समर्पण के लिए जाना जाता है। ऐसे में राजनीति के गलियारों में यह तीखी बहस छिड़ गई है कि इस मौके पर असल कुर्बानी किसने दी और किसे क्या मिला?



डीके शिवकुमार की आँखें नम थीं और उन्होंने सिद्धारमैया के पैर छुए और दोनों नेता एक-दूसरे के गले लग गए। संयोग देखिए कि यह सब कुछ बकरीद के आसपास हो रहा है। एक ऐसा त्योहार जो अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी और समर्पण के लिए जाना जाता है। ऐसे में राजनीति के गलियारों में यह तीखी बहस छिड़ गई है कि इस मौके पर असल कुर्बानी किसने दी और किसे क्या मिला?

एक बेहद कद्दावर और जनाधार वाले नेता का खुद अपनी चलती-चलाती कुर्सी को छोड़ देना और खुद अपने हाथों से शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखना, राजनीति में एक बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी है। कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर तैयार किए गए इस पूरे दृश्य के जरिए ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जिस तरह कुर्सी के लिए आलाकमान को पसीने ला दिए थे, सिद्धारमैया ने उससे बिल्कुल अलग मिसाल पेश की। उन्होंने आलाकमान के फैसले को सिर-आंखों पर रखते हुए हंसते-हंसते अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी।

राहुल गांधी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है वो यह है कि वह फैसले नहीं लेते मतलब स्टेटस को बनाए रखते हैं और उनका फैसला ना लेना भी एक तरीके से एक फैसला ही होता है। पर अब वे निर्णय लेने लगे हैं। फैसले का जोखिम जानते हुए भी कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। पार्टी का भला होगा या बुरा होगा। केरल के मुख्यमंत्री के लिए केसी वेणुगोपाल के बदले वीडी सतीशन को तरजीह देना। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की समर्थन देने में भी उनकी अहम भूमिका रही और अब कर्नाटक में डीके शिवकुमार का पक्ष चुनकर कांग्रेस ने इन दिनों अलग तरह की राजनीतिक राह पकड़ी है। एक कहानी कांग्रेस के अंदर और बाहर भी चल पड़ी थी जिसको बीजेपी भी खूब हवा दे रही थी कि राहुल गांधी को राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं है। वह फैसले नहीं लेते। खासतौर से जब बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी तो राहुल गांधी के एक बयान की दबे-छिपे जुबान में खूब चर्चा हुई। दावा किया जाता है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि टॉक टू वेणु यानी केसी वेणुगोपाल से बात कर लीजिए सीटों के शेयरिंग से मेरा क्या लेना देना है यानी जब बड़े फैसले की घड़ी होती थी तो राहुल के बारे में ये कहा जाता था कि वो कोई फैसला ही नहीं लेते थे। लेकिन इन दिनों एक नए राहुल गांधी जो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और सही समय पर ले रहे हैं सही समय अभी तो लग रहा है कल क्या होगा कह नहीं सकते पर राहुल ने साबित कर दिया है कि अब वह फैसले लेने वाले एक परिपक्व नेता देता है। इसे आप तीन फैसलों के जरिए समझ सकते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, फिर केरल और अब कर्नाटक तीनों फैसलों पर आने से पहले एक चीज जिस पर आप गौर करेंगे वो राहुल का लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेना।

ताजा मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक पर फैसला लेने से पहले राहुल गांधी ने सबसे बात की। उन्होंने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार उन दोनों को दिल्ली बुलाया। उनसे बात करने से पहले उन्होंने संगठन में महामंत्री केसी वेणुगोपाल सेबातचीत की उसके बाद वहां के जो प्रभारी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला उनसे बात की। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राय मशवरा करने के बाद ये निर्णय लिया। इसमें सबसे खास बात ये है कि उन्होंने कोई आदेश नहीं जारी किया। उन्होंने एक फार्मूला बनाया। केरल में सब जानते थे जो विधायकों की संख्या है मतलब मेजॉरिटी माना यही जाता है कि जो जितने विधायकों का समर्थन जिस नेता के पास होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उन्होंने बीडी सतीशन को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना क्योंकि वो जानते थे कि केरल में एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसको चुना जाए और जिससे किसी तरीके से राहुल गांधी पर आरोप ना लगे। पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने रमेश सैनीथल्ला से भी बात की।

कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है और वहां इस वक्त जो हो रहा है, वह उसकी बदली हुई रणनीति का संकेत है। पार्टी अब जिस राजनीतिक मॉडल पर काम कर रही है, उसमें जहां कांग्रेस संगठन मजबूत है, वहां वह सीधा मुकाबला करेगी। लेकिन जहां स्थिति गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की मदद लेगी। साथ ही, वह क्षेत्रीय नेतृत्व को भी मजबूत करेगी। कांग्रेस पिछले वर्षों में कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। इससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हुआ है। पार्टी की चुनावी रणनीति बेअसर रही है। ऐसे में लगता है कि वह बीजेपी के रास्ते पर चलने जा रही है। बीजेपी देश में विस्तार के लिए कई तरीकों पर काम करती है। मसलन, जहां वह मजबूत है, वहां अकेले सरकार बनाना, कमजोर राज्यों में गठबंधन करना और फिर उस राज्य में पार्टी को मजबूत करके छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आना। जहां पार्टी मजबूत नहीं है, वहां विपक्ष के कद्दावर नेता को बीजेपी में शामिल करवाना और फिर उसे आगे करके चुनाव लड़ना। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार में यही देखा गया और हिमंता बिस्वा सरमा, शुभेंदु अधिकारी और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया। फिर बीच-बीच में नेतृत्व को बदलना ताकि हर कार्यकर्ता और नेता को मौका मिल सके और पार्टी को फायदा हो। अब कांग्रेस भी उसी पथ पर चलने की कोशिश कर रही है।

कर्नाटक में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के ठीक बीच, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन नायक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बहुप्रतीक्षित कास्ट सर्वे रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि, इस रिपोर्ट की टाइमिंग और इसका बैकग्राउंड बेहद पेचीदा है। यह रिपोर्ट काफी पुरानी है और दो साल पहले भी इसे लेकर राज्य में खासा विवाद हो चुका है। कर्नाटक के दो सबसे प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से मजबूत समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत ने इस रिपोर्ट पर ठीक वैसे ही सवाल उठाए हैं, जैसे बिहार की जातिगत गणना को लेकर अदालतों और राजनीतिक गलियारों में कठघरे में खड़ा किया गया था। दोनों ही प्रभावशाली समुदायों के नेताओं का साफ आरोप है कि यह सर्वे पुराना हो चुका है और इसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं किया गया है। खुद वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए इस विवादित रिपोर्ट को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। हंसते हुए विदा होने वाले सिद्धारमैया ने इस एक फैसले से शिवकुमार के सामने एक बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क खड़ा कर दिया है।

पुराण दिग्दर्शन ....



सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसलिये राजा वेन के शरीर से संतान उत्पन्न करना न असम्भव है, न प्रकृति के प्रतिकूल ही है।

अरणी काष्ठ से शुक जन्म

कहा जाता है कि- यज्ञार्थ अग्निमन्थन करते हुवे व्यास जी का वीर्य घृताची अप्सरा को देख कर अरणी नामक लकड़ी में गिर गया, जिससे शुकदेव जी का जन्म हुआ- यह कथा कोरी गप्प है।

पौराणिक स्वरूप

(क) मेरुशृङ्ग महारम्ये व्यासः सत्यवतीसुतः।
तपश्चचार सोऽत्युग्रं पुत्रार्थकृतनिश्चयः ॥14॥
गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः।
उत्तिष्ठ वासवीपुत्र ! पुत्रस्ते भविता शुभः।।16।।
शूलपाणि नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः।।22।।
अरणीसहितं गुह्यं ममन्थाग्निचिकीर्षया।
मन्थनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिन्ताभवत्तदा।। 23।।
पावकस्य यथा तद्वत्कथं मे स्यात्सुतोद्भवः।
पुत्रारणी तु याख्याता सा ममाद्य न विद्यते।। 25।।
एवं चिन्तयतस्तस्य घृताचो दिव्यरूपिणी ॥36।।
प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता ।।30।।
पंचबाणपरीताङ्गस्तूर्णमासीद्धृतव्रतः ।।31।।
(देवी भागवत 1 । 10)

(ख) सा कृत्वाथ शुकीरूपं निर्गता भयविह्वला ।।3।।
अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमथापतत् ।।7।।
तस्माच्छुकः समुद्भूतो व्यासाकृतिः मनोहरः ।।8।।
(देवी भागवत 1 । 14)

अर्थात् (क) मेरु पर्वत की रमणीय चोटी पर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन तपश्चर्या आरम्भ की ॥14।। (तप से प्रसन्न होकर) जगद्गुरु महादेव जी ने व्यास के निकट जाकर कहा कि हे पुत्र ! उठ, तेरे कल्याणकारी पुत्र उत्पन्न होगा ।।16।। व्यास जी नहादेव को नमस्कार करके अपने आश्रम में आ गये ॥ 22।।

क्रमशः ...

हिन्दी पत्रकारिता दिवस

संजय गोस्वामी

पत्रकारिता समाचारों, विचारों और घटनाओं को एकत्र करके उन्हें जनता तक पहुँचाने का माध्यम है, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक, निष्पक्ष और सूचित रखना है इंसानी इतिहास में, पत्रकारिता ने अपनी अहम जगह और ऊँचे आदर्शों पर पक्के भरोसे के ज़रिए हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत में, पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ साल पुराना है। आज, पत्रकारिता शब्द हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सुबह होते ही हमें अखबार की ज़रूरत महसूस होती है; इसके बाद, पूरे दिन हमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे अलग-अलग तरीकों से खबरें मिलती रहती हैं। इसके अलावा, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते हैं। इस लगातार जुड़ाव के पीछे एक खास इच्छा है—एक



जिज्ञासा—नई और ताज़ा जानकारी पाने की। लोग पिछले कुछ घंटों में या पिछली रात से हुए बदलावों या सामने आई नई घटनाओं के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। इस बात का निचोड़ यह है कि हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और साथ काम करने वालों से अपने आस-पास हो रही घटनाओं के बारे में लगातार जानना चाहते हैं। अपने आस-पास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में अप-टू-डेट जानकारी पाना इंसान की एक जन्मजात आदत है; जिज्ञासा की भावना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। यही जिज्ञासा न्यूज़ का बुनियादी हिस्सा है—और, बड़े पैमाने पर कहें तो, खुद पत्रकारिता का भी। अगर यह जिज्ञासा खत्म हो जाए, तो न्यूज़ की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता इसी अंदरूनी जिज्ञासा को पूरा करने की कोशिश के तौर पर शुरू हुआ—यह एक ऐसा मिशन है जिसे यह आज भी पूरा कर रहा है, और अपने बुनियादी उसूलों पर मज़बूती से टिका हुआ है। इस जिज्ञासा के ज़रिए, हमें अपने आस-पड़ोस, शहर, राज्य और पूरी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। यह जानकारी न सिर्फ़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बल्कि पूरे समाज पर असर डालती है। इसके अलावा, यह जानकारी हमारे अगले कदम को तय करने में हमारी मदद करने में भी अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि आज के समाज में इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मीडिया का महत्व तेज़ी से बढ़ा है। आज, हम देश और दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में ज़्यादातर जानकारी अलग-अलग न्यूज़ मीडिया आउटलेट से लेते हैं। इन अलग-अलग चैनलों के ज़रिए—चाहे वह अखबार हों, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, या सोशल मीडिया—दुनिया भर की खबरें सीधे हमारे घरों तक पहुँचती हैं। न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने वाले जर्नलिस्ट लोकल और ग्लोबल लेवल पर होने वाली घटनाओं को न्यूज़ रिपोर्ट में बदलते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। ऐसा करने के लिए, वे रोज़ाना जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे न्यूज़ फ़ॉर्मेट में ढालते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पत्रकारिता कहते हैं। कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति, समाज, देश या पूरी दुनिया पर असर डालती है, वह न्यूज़ होती है। दूसरे शब्दों में, किसी खास घटना पर रिपोर्ट, डेफिनिशन के हिसाब से, न्यूज़ है।

कश्मीर को लेकर चीन-पाकिस्तान को करारा संदेश

कांतिलाल मांडोत

जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट, दृढ़ और अटल रही है। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और रहेंगे। चीन और पाकिस्तान द्वारा जारी संयुक्त बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया कड़ा जवाब केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और क्षेत्रीय अखंडता की स्पष्ट घोषणा थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन और पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की असफल कोशिश करता रहा है। उसे यह भय सताता है कि यदि दुनिया ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह भारत का हिस्सा मान लिया तो उसका दशकों पुराना प्रचार तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। दूसरी ओर चीन भी अपनी सामरिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत शुरू से इस परियोजना का विरोध करता आया है क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत का स्पष्ट मत है कि जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है वहां किसी तीसरे देश की परियोजना स्वीकार नहीं की जा सकती।

चीन और पाकिस्तान यह भलीभांति जानते हैं कि यदि उन्होंने कश्मीर और लद्दाख का नाम लेना बंद कर दिया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाएगा कि ये क्षेत्र पूरी तरह भारत के ही अंग हैं। यही कारण



है कि दोनों देश समय समय पर संयुक्त बयान जारी कर इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान के पुराने दुष्प्रचार को गंभीरता से नहीं लेती। अधिकांश देशों ने यह समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक विषय है और इसका समाधान भारत अपने संवैधानिक ढांचे के भीतर ही करेगा।

भारत ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के दायरे में लाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में दिखाई देता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश वैश्विक शक्तियों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार चीन का सहारा लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है।

चीन का रवैया भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। वह एक ओर भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को सामरिक सहयोग देकर दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर काम करता है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो चुका है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।

भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने में रुचि दिखा रही हैं। चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो या पश्चिम एशिया के देश, सभी भारत को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे देशों की आर्थिक मदद पर निर्भर है। ऐसे में भारत को चुनौती देना उसके लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी भर रह गया है।

भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमेशा सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में खुफिया एजेंसियों द्वारा अल बद्र और हिजबुल मुजाहिदीन के संभावित गठजोड़ को लेकर जारी अलर्ट इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए हुए है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले संगठनों को समर्थन देती रही है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर इन संगठनों की कमर तोड़ दी है।

आज घाटी में विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़कें बन रही हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, निवेश आ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यही बदलाव पाकिस्तान और उसके समर्थकों को सबसे अधिक परेशान करता है। वे नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, क्योंकि इससे उनका झूठा प्रचार कमजोर पड़ता है। इसलिए समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय बयानबाजी के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है।

भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि बातचीत और शांति तभी संभव है जब आतंकवाद पूरी तरह बंद हो। एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात करता है और दूसरी तरफ आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देता है। यह दोहरा चरित्र अब दुनिया से छिपा नहीं है। भारत की नीति साफ है कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते।

चीन और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि नया भारत हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। भारत केवल सैन्य शक्ति के आधार पर ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक कूटनीति के दम पर भी मजबूत हुआ है। भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की जनता भी राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर पूरी मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत की पहचान, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा हैं। इन्हें भारत से अलग देखने की कल्पना भी असंभव है। चीन और पाकिस्तान चाहे जितने संयुक्त बयान जारी कर लें, चाहे जितने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शोर मचा लें, इससे जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सर्वोपरि है और इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों को पहचानें और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करे। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। यही संदेश भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया है और यही संदेश आने वाले समय में भी पूरी दृढ़ता के साथ दोहराया जाता रहेगा।

आज का इतिहास

1910 जनरल लुइस बोथा दक्षिण अफ्रीका संघ के पहले प्रधानमंत्री बने।
1913 लंदन की संधि पर प्रथम बाल्कन युद्ध के समापन से उत्पन्न होने वाले प्रादेशिक भेदभावों से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, अन्य बातों के अलावा, एक स्वतंत्र अल्बानिया।
1919 ब्रिटिश ने 1915 में नाइट टाइटल के साथ रवींद्रनाथ टैगोर को ताज पहनाया, लेकिन जलियांवाला बाग में हुई घटना के बाद, रवींद्रनाथ टैगोर ने आतंक का विरोध करने के लिए 1919 में नाइट टाइटल को आगे रखने से मना कर दिया।
1925 शंघाई म्युनिसिपल पुलिस के अधिकारियों ने शहर के अंतर्राष्ट्रीय निपटान में चीनी उत्पादकों पर गोलियां चला दीं, जिससे अमाजोर श्रम और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को बढ़ावा मिला।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध: एक हजार ब्रिटिश हमलावरों ने कोलोन, जर्मनी पर 90 मिनट का हमला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा 262 अलग-अलग हवाई हमलों में जर्मन शहर कोलोन में बमबारी की गई थी। आरएएफ द्वारा शहर पर कुल 34,711 लंबे टन बम गिराए गए।
1948 कोलंबिया नदी को पकड़ने वाली एक खाई टूट गई, जिससे बाढ़ आई जिसने वनपोर्ट, ओरेगन, अमेरिका को नष्ट कर दिया, इसके निर्माण के केवल पांच साल बाद।
1959 न्यूजीलैंड के पूर्व नॉर्थ शोर शहर के ऑकलैंडविथ नॉर्थकोट में सेंट मेरीज़ बे में शामिल होने वाला ऑकलैंड हार्बर ब्रिज, खुल गया।
1961 डोमिनिकन स्ट्रॉन्ग राफेल ट्रूजिलो को जनरलों के एक समूह ने घात लगाकर हत्या कर दी थी।
1962 चिली में 1962 का फीफा विश्व कप की शुरुआत हुआ।
1963 बौद्ध संकट दक्षिण-वियतनाम की नेशनल असेंबली के बाहर कैथोलिक भेदभाव के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति एनगोन के खिलाफ पहला खुला प्रदर्शन
1967 चुक्उमेमेका ओडुमग्वु ओजुकु ने दक्षिणपूर्वी नाइजीरिया में एक अलगाववादी राज्य बियाफ्रा की स्थापना की घोषणा की, एक सप्ताह बाद नाइजीरियाई गृहयुद्ध शुरू हो गया।
1972 जापानी रेड आर्मी के सदस्यों ने इजरायल के तेल अवीव में लोद एअरपोर्टमैसरे को लोकप्रिय मोर्चे की ओर से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए किया, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 80 अन्य घायल हो गए।
1975 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ।
1990 पेरू में भूकंप से 135 लोगों की मौत हुई।

भारत के साथ खड़ा हो गया चीन! पाकिस्तान हैरान

नीरज कुमार दुबे

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर के चीन दौरे से लौटते ही चीन ने एक बड़ा सामरिक और कूटनीतिक खेल खेल दिया। एक ओर बीजिंग में पाकिस्तान के साथ चीन ने अपने रिश्तों को अटूट बताते हुए सुरक्षा, रक्षा और पश्चिम एशिया में साझा रणनीति पर खुला समर्थन दिया, वहीं दूसरी ओर उसी समय भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रचनात्मक और भविष्य उन्मुख वार्ता कर संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत भी दे दिया।

हम आपको बता दें कि बीजिंग में भारत और चीन के बीच परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र की बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानि एलएसी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता रचनात्मक और भविष्य उन्मुख रही तथा दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर शांति बनाए रखने से द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रगति संभव हुई है।

यह बैठक ऐसे समय हुई जब 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पैदा हुए लंबे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में दोनों देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद देपसांग और डेमचोक जैसे अंतिम तनाव वाले क्षेत्रों में भी सैनिकों की वापसी का समझौता हुआ था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान और तियानजिन में हुई बैठकों ने रिश्तों को नई दिशा देने का प्रयास किया। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ संबंध आगे बढ़ाना चाहता है।

दूसरी ओर चीन ने पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का खुला संकेत दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को पुराना मित्र बताते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान की मित्रता अटूट है। उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन का भरोसा दोहराया। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान की उस भूमिका की भी सराहना की जिसमें उसने पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को सुरक्षा सहयोग और अधिक व्यापक बनाना चाहिए तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए



साथ मिलकर काम करना चाहिए।

हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का यह दौरा केवल औपचारिक नहीं था। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, कृषि और सुरक्षा सहयोग से जुड़े पंद्रह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अगले चरण को तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिया। साथ ही पाकिस्तान ने चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की यह दोहरी रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ वह पाकिस्तान को अपने सबसे भरोसेमंद सामरिक साझेदार के रूप में मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ सीमा पर तनाव कम करके एशिया में स्थिरता बनाए रखना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह अमेरिका के रणनीतिक खेमे में चला जाए। इसलिए वह सीमा विवाद को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है।

इसी बीच, सिंगापुर में जारी एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन रिपोर्ट ने भी भारत की सामरिक चुनौतियों को रेखांकित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए पारंपरिक सैन्य खतरे का केंद्र आगे भी चीन और पाकिस्तान ही रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति ऐसी है जिसमें न युद्ध है और न पूर्ण शांति। भारत अपनी सेना को बड़े पारंपरिक युद्धों के लिए तैयार कर रहा है क्योंकि उसे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की सैन्य नीति लगातार विकसित हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ 2016, 2019 और 2025 में की गई कार्रवाईयों ने उसकी रणनीतिक सोच को नया रूप दिया है। दूसरी ओर चीन हिंद महासागर क्षेत्र और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे एशिया में शक्ति संतुलन का नया दौर शुरू हो गया है।बहरहाल, चीन ने एक ही समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ सक्रिय कूटनीतिक चाल चलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ और प्रभाव को हर हाल में बनाए रखना चाहता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार की आक्रामक और संतुलित कूटनीति ने चीन को भी अपने रुख में नरमी लाने के लिए मजबूर किया है। गलवान संघर्ष के बाद भारत ने जिस मजबूती से सीमा पर सैन्य दबाव बनाया, आर्थिक मोर्चे पर सख्ती दिखाई और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत की, उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि चीन एक तरफ पाकिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ संबंध सामान्य करने के लिए लगातार संवाद बढ़ा रहा है। भारत ने यह संदेश दे दिया है कि नया भारत दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बातचीत करने वाला देश है। आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां निश्चित रूप से भारत के लिए चुनौती रहेंगी, लेकिन मोदी सरकार की रणनीतिक तैयारी, सैन्य मजबूती और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता ने भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दी है।

पंजाब में विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चाएं और संभावना

इकबाल सिंह चन्नी

पंजाब की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि क्या विधानसभा के चुनाव अपने निर्धारित समय से पहले करवाए जा सकते हैं? हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों, टी.वी. बहसों और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। समयपूर्व चुनाव होने की चर्चाओं के लिए केवल राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि देश के अंदर चल रही एस.आई.आर., जनगणना और मौसम भी शामिल हैं। यह चर्चा क्यों शुरू हुई, इसे समझने के लिए हमें ऊपर दिए गए बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं क्योंकि सुखबीर सिंह बादल द्वारा लगातार रैलियां की जा रही हैं, 'आप' द्वारा पंजाब में 16,000 रैलियां करने का ऐलान किया गया है, कांग्रेस भी बड़ी रैलियां कर रही है और भाजपा भी मोगा में अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी रैली करके चुनावी बिगुल बजा चुकी है। बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अपने-अपने तौर पर तैयारी कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियों की इन गतिविधियों को देखकर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इसके अलावा एस.आई.आर. की प्रक्रिया शुरू होने को भी जल्दी चुनाव करवाने से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले मौसम के कारण पेश आने वाली प्रशासनिक दिक्कतों और विद्यार्थियों की परीक्षाओं की डेटशीट को भी ध्यान में रखता है, जैसे कि जुलाई-अगस्त के महीने में बाढ़ आने और कई इलाकों में पानी भरने की समस्याएं आ जाने के कारण बरसाती मौसम में चुनाव कराने से बचा जाता है। सर्दियों के चरम (पीक) समय में भी आमतौर पर चुनाव नहीं करवाए जाते क्योंकि इस मौसम में धुंध के कारण सुरक्षा और आवाजाही की समस्या आने का खतरा बना रहता है। जनगणना का पंजाब विधानसभा के चुनावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है या नहीं, अब इस बारे में विचार करते हैं। जनगणना का दूसरा और आखिरी महत्वपूर्ण चरण 9 फरवरी को शुरू होगा। जनगणना की प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी की जानी है। 1 मार्च की रात को 12 बजे सरकार देश की जनसंख्या की गिनती का आधिकारिक तौर पर ऐलान करेगी। लेकिन यह प्रक्रिया 5 मार्च तक भी चल सकती है, क्योंकि कई जगहों पर रिवीजन राऊंड की जरूरत पड़ती है, जिस कारण सरकारी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा 5 मार्च तक इसी काम में व्यस्त होगा। यदि ऊपरोक्त कारणों पर नजर डालें तो यह लगता है कि पिछले चुनावों के मुताबिक फरवरी में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने लगभग मुश्किल लगते हैं क्योंकि जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी को शुरू होने के कारण मुलाजिमों को कम से कम जनवरी के आखिरी हफ्ते में जनगणना के काम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्रामों में शामिल होना पड़ेगा। इस तरह 5 मार्च को जनगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव करवाना संवैधानिक मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि 5 मार्च के बाद यदि चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, तो पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

शरद पवार का सुझाव देश के हित में है

अवधेश कुमार

शरद पवार ने देश की विदेश नीति पर आंतरिक राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में जो कुछ कहा है उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन जब देश के सम्मान की बात आती है तो राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर भारत के अंदर राजनीतिक व गैर-राजनीतिक मोर्चे पर हो रही टिप्पणियों के संदर्भ में उनका यह मंतव्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात से आरंभ कर स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और इटली की द्विपक्षीय यात्रा की तथा नार्वे की राजधानी ओस्लो में स्कैंडिनेवियाई भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री के समक्ष अपने राष्ट्रीय हित को साधने का उद्देश्य था और इन यात्राओं पर विशेषज्ञों का मत यही है कि उसमें उन्हें अधिकतम सफलता मिली। किंतु राजनीतिक और गैर-राजनीतिक एक्टिविज्म और सोशल मीडिया पर उनके विदेश में रहते हुए ही हमले शुरू हो गए। सारे हमलों व आलोचनाओं के हल्ला बोल में ऐसा एक तथ्य सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि अमुक बिंदू पर प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय हित के अनुकूल काम नहीं किया। जाहिर है कि विरोध केवल राजनीतिक मतभेदों और असहमतियों के इर्द-गिर्द था। यह चिंताजनक है क्योंकि भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर की राजनीतिक असहमतियां और मतभेद सीमाओं से बाहर चला जाए तो राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। इसका अर्थ है कि हम देश हित को प्राथमिकता देने की जगह अपने राजनीतिक, व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता दे रहे हैं या फिर हमारा वैचारिक दुराग्रह हावी है।

ऐसा नहीं है कि पवार की मोदी से पूरी तरह सहमति है। महाराष्ट्र में आज शरद पवार की राकांपा शक्तिहीन है तो



इसी कारण क्योंकि स्वर्गीय अजीत पवार ने विद्रोह कर भाजपा से हाथ मिला लिया। बावजूद हमारी पारंपरिक राजनीति, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले गिने-चुने नेता रह गए हैं, में यही व्यवहार लंबे समय तक रहा है। देश में हमारी असहमति होती है, आरोप-प्रत्यारोप करते हैं लेकिन जब विदेशों की, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आती है तो देश साथ खड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या विदेश में प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां केवल राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। एक भारतवासी के नाते इस समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। पश्चिम एशिया संकट यानी ईरान-अमरीका-इसराईल टकराव और तनाव ने ईंधन आपूर्ति में उथल-पुथल पैदा कर दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य की खतरनाक नाकेबंदी से निपटना विश्व के लिए मुश्किल हो रहा है। इसमें पैट्रोल-डीजल आदि के लिए आयात पर निर्भर भारत या अन्य देशों के लिए दूरगामी दृष्टि से आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था करना, देशों के संबंधों में हो रहे बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या अस्थिरता के काल में उसका आधार बनाते रहना तथा भविष्य में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की दृष्टि से ऐसी स्थिति में होना ताकि देश के रूप में हम कहीं अलग-थलग न पड़ें।

प्रधानमंत्री की यात्रा में यही लक्ष्य समाहित होंगे। इन सबमें यहां विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। आप चाहे भाजपा सरकार के विरोधी हों या समर्थक दृष्टि एक ही होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान उन देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडलों की बातचीत, संयुक्त घोषणाओं तथा संपन्न समझौतों में क्या-क्या हुआ। जब आप गहराई से उन सबको देखेंगे तो आपका विचार अपने आप बदल जाएगा। दुर्भाग्य से हम उन पर सरसरी दृष्टि भी डालना नहीं चाहते। इस यात्रा में स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और काम करने वाली पत्रकार और कार्टून छापने वाले अखबार के देश नॉर्वे ने भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य और कृषि संगठन ने प्रधानमंत्री को विशेष रूप से सम्मानित किया। इन सब पर चर्चा की जगह हमारे यहां टॉफी वीडियो को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं जिनमें कई को देखने सुनने या पढ़ने में शर्म आए। भारत जैसे देश में विमर्श का यह स्तर किसी को भी अंदर से परेशान कर देगा।

क्या हम ऐसा करते समय विचार भी नहीं करते कि एक देश के रूप में विदेश में हमारी कैसी छवि बनेगी। यहीं पर शरद पवार का यह कथन प्रासंगिक हो जाता है कि जब भी राष्ट्रीय हित के लिए सामूहिक रूप से काम करने का मौका मिले तो सभी को एक सांझा उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री देश के बाहर होते हैं तो अपने दृष्टिकोण से वह देश के भविष्य और सम्मान को ही केंद्र में रखते हैं। कई बार इनमें गलतियां भी हुई हैं। आज के दौर के अनुसार उनकी आलोचना भी अस्वाभाविक नहीं है किंतु आलोचना तथ्यों के आधार पर होगी। आखिर जॉर्जिया मेलोनी को मैलोडी ट्रॉफी भेंट करने से हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचा।

कूटनीति में एक सामान्य वस्तु का उपयोग कर माहौल बदल देना, दुनिया को संदेश देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर व्यवहार का रास्ता दिखा देना सामान्य बात नहीं है। भारत ने अपने लक्ष्य के अनुरूप यात्रा से सारी उपलब्धियां हासिल कीं जिसकी ओर तत्काल दृष्टि थी। दूसरे देश भी अपने हित के अनुसार काम कर रहे थे। पर मूल बात यह है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता अब ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं कि सामने आकर रास्ता दिखाएं। ज्यादातर जा चुके हैं। हमें ही अपने हर व्यवहार पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देकर स्वयं को बदलना होगा।

मुक्त वैश्विक व्यापार के पक्ष में क्वाड देश

अनिल त्रिगुणायत

वैश्विक सप्लाई चेन्स, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह की आपूर्ति में आयी रुकावट की पृष्ठभूमि में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक को एक्शन-ओरिएंटेड किया गया कि किस तरह से हिंद-प्रशांत मुक्त और अबाध हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देने का सारे क्षेत्र पर फर्क पड़ा है। पूरा सप्लाई चेन बाधित हुआ है। फर्टिलाइजर से लेकर हीलियम और कितनी ही और चीजों की आवाजाही रुक गयी है, जिससे आर्थिक सुस्ती जैसी स्थिति है।

क्वाड के देशों ने यह महसूस किया कि अगर हिंद-प्रशांत में इस तरह की हरकतें होती रहीं, तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। होर्मुज से तो 20 फीसदी ही व्यापार होता है, जबकि विश्व व्यापार का 60 फीसदी हिंद-प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पर बाधा खड़ी कर दी जाती है, तो कितना नुकसान हो सकता है। इस बैठक में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल हुए।

क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी, ऊर्जा सुरक्षा तथा क्रिटिकल मिनरल्स के उत्खनन, शोधन तथा आपूर्ति शृंखला को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। बैठक में तीन पहल की गयी। क्वाड साझेदारों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों की समुद्री निगरानी का लाभ उठाने के लिए पहली बार हिंद-प्रशांत क्षेत्र समुद्री निगरानी गठजोड़ पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सूचना साझा करना और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता क्षमता बढ़ाना है, जिसमें शुरुआती ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित होगा। दूसरी पहल है, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा। यह फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए निवेश में तालमेल बिठाने में मदद करेगा। इसको कैसे सोर्स करेंगे, कैसे उसमें वैल्यू क्रिएशन करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग होगी, इन सारी चीजों पर विचार-विमर्श हुआ है।

तीसरी पहल के तहत क्वाड देशों ने हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने में मदद करना है।



क्वाड देशों ने वाणिज्यिक जहाजों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की और नौवहन की स्वतंत्रता तथा निर्बाध वैश्विक व्यापार की बात कही। सबको पता है कि नौवहन की स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री रास्ते में आवाजाही अगर रुकती है, तो उसका क्या असर होता है, यह दुनिया ने अस्सी दिनों में देख लिया है। समुद्री परिवहन बाधित होने से दुनियाभर में ईंधन, भोजन और उर्वरक की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। क्वाड ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए फिजी के साथ काम करने की घोषणा की, तो डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए प्रशांत द्वीप देशों में अंडर सी केबल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन दोहराया।

भारत और अमेरिका ने भी क्रिटिकल और रेयर अर्थ सप्लाई फ्रेमवर्क के तहत अलग से एक समझौते पर दस्तखत किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस समझौते को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समझौता सुदृढ़ और विविधतापूर्ण आपूर्ति शृंखला को मजबूत करेगा, साथ ही, हमें सहयोग करने, वित्तपोषण जुटाने और महत्वपूर्ण व दुर्लभ खनिजों के प्रभावी प्रबंधन में मदद करेगा। जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना था कि हमारे रणनीतिक हित इसमें हैं कि हमें जरूरी खनिजों और आपूर्ति शृंखला तक भरोसेमंद और लंबे समय तक पहुंच मिलती रहे। इस समझौते की नींव विगत फरवरी में रखी गयी थी, जब विदेश मंत्री जयशंकर वाशिंगटन में आयोजित 'क्रिटिकल मिनरल्स फोरम' में शामिल हुए थे। उसके बाद इसने और तेजी तब पकड़ी, जब भारत ने 'पैक्स सिलिका' पर दस्तखत किये। जाहिर है, क्वाड की बैठक में ईरान के अलावा चीन भी निशाने पर रहा। लेकिन चीन का किसी ने भी नाम नहीं लिया। हालांकि बैठक में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी पर बात हुई। और इस पर तो कोई शक ही नहीं है कि हिंद-प्रशांत में चीन का जो रवैया है, उसको लेकर क्वाड के अंदर चिंता तो है ही।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक में नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत खुलकर बोला गया है, क्योंकि उसके आक्रामक रवैये और मिसाइल हमले की धमकी चिंताजनक है। और ऐसा लगता है कि जापान ने इसे गंभीरता से लिया है। लेकिन सारे देशों के चीन के साथ संबंध इस वक्त काफी हद तक सुधरे हैं। चाहे वह अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो। चीन के रवैये पर सबको शक है, सबको परेशानी है, कुछ-न-कुछ शिकायतें भी हैं। इसके बावजूद ये सारे देश चीन से संबंध सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। खुद चीन भी इन देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। तो तकरार की जगह समझने-समझाने का जो अप्रोच है, उसकी कोशिश हो रही है। अभी-अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का दौरा किया है। उस दौरान उन्होंने चीन की तारीफ की। ऐसे में, क्वाड की बैठक में भला कौन-सा देश चीन के खिलाफ खुलेआम बोलता?

क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की सफलता का एक और पैमाना यह है कि ब्रिक्स की बैठक के विपरीत, इसमें साझा बयान जारी किया गया है, जो काफी विस्तृत है। ब्रिक्स की बैठक में समस्या यह थी कि यूएइ और ईरान, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे देश थे, लिहाजा आपसी सहमति बनना कठिन था। क्वाड में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें किसी की किसी से लड़ाई नहीं है।

कुल मिलाकर, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक सफल रही। बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि इस बैठक के जरिये क्वाड जैसे संगठन की प्रासंगिकता फिर से साबित हुई है। अभी तक यह चल रहा था कि ट्रंप रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन बात उससे आगे बढ़ी है। जहां तक क्वाड के शिखर बैठक की बात है, तो वह टाइम शेड्यूलिंग पर निर्भर करेगा कि उसका आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो पाता है या नहीं। शिखर बैठक का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी बहुत हद तक निर्भर करेगा। देखने वाली बात यह है कि भारत के पास ब्रिक्स की भी अध्यक्षता है और हमने दोनों संगठनों को कुशलता से संभाल रखा है।

आखिर क्यों ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं बंगाल सीएम शुभेन्दु?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बंगाल की डबल इंजन सरकार अब विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सहित अभी केवल छह सदस्य हैं, लेकिन सरकार की कार्यशैली और निर्णय लेने की गति ने राजनीतिक गलियारों में अलग ही संदेश दिया है। बंगाल सरकार अभी अपने शुरुआती चरण में है और तीन सप्ताह भी नहीं हुए हैं, लेकिन फैसलों की गति और प्रशासनिक सक्रियता ने यह संकेत जरूर दिया है कि बंगाल की राजनीति और विकास मॉडल दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्षों से लंबित केंद्रीय योजनाओं को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से रुकी परियोजनाओं की सूची मांगी गई है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

ताबड़तोड़ फैसले और सीएम का सिंघम स्टाइल-

● बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण - सीमा सुरक्षा मजबूत करने हेतु बड़ा फैसला लिया गया।

● चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस संवेदनशील इलाके की करीब 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपने का फैसला।

● गौवंश की बलि पर पूर्ण प्रतिबंध और साथ ही अन्य पशुओं के वध के लिए अब फिटनेस अथवा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कलकत्ता हाइकोर्ट का भी राज्य सरकार के इस नए आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार।

● आरजीकर लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की फाइल फिर से खोलना। तीन आईपीएस अधिकारियों के सस्पेंड होने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई की नई टीम को जांच का आदेश।

● तृणमूल सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा पीड़ित परिवारों के समर्थन और साथ खड़े होने का आश्वासन देते हुए सरकारी नौकरी देने की घोषणा।

● राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी - प्रशासनिक और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया।

● भ्रष्टाचार मामलों में सीबीआई कार्रवाई को अनुमति - शिक्षक भर्ती, नगरपालिका और सहकारी घोटालों में अभियोजन की मंजूरी दी गई।

सरकार के इन निर्णयों पर भी करें गौर

● महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला। मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत लखी भंडार/अन्नपूर्णा योजना को बढ़ी हुई राशि के साथ 1 जून से शुरू करने की घोषणा।

● आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय - लंबे समय से रुकी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

● 5 रुपए में मछली भात योजना - गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए सस्ती भोजन योजना की घोषणा।

● स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों पर रोक - सामाजिक वातावरण सुधारने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया।

● आयुष विभाग को अलग प्रशासनिक पहचान - आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अलग करने का फैसला।

● पीएम विश्वकर्मा योजना का बंगाल में विस्तार - कारीगरों और पारंपरिक श्रमिकों के लिए केंद्र की योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज की गई।

● प्रशासनिक बैठकों में विपक्षी दलों के सांसद और विधायकों को आमंत्रित करना। विकास से कोई इलाका अछूता नहीं रह पाए।

बहरहाल, बंगाल सरकार और भाजपा नेतृत्व लगातार यह संदेश दे रहा है कि डबल इंजन सरकार का अर्थ विकास की दोगुनी रफ्तार और योजनाओं के तेज क्रियान्वयन से है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, मुख्यमंत्री शुभेंदु और अन्य नेताओं ने भी बंगाल में तेज विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और निवेश बढ़ाने का दावा किया है।



ये आदतें नष्ट कर देती हैं शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता

आदतें ही होती हैं जो हमारे जीवन, सेहत और चरित्र आदि का निर्माण करती हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको एक आदर्ष जीवशैली और अच्छी आदतों का पालान करना होता है। जिसमें नियमित व्यायाम व पौष्टिक आहार आदि शामिल होते हैं। इस तरह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर रोगों से दूर रहता है। वहीं हमारी जीवनशैली से जुड़ी खराब आदतें हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन कुछ खराब आदतें ऐसी भी होती हैं, जिनसे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता खतम हो जाती है।

अकसर जाने-अनजानें हमारी कई आदतें हमें कई रोगों की ओर ढ़केल देती हैं। इन आदतों के चलते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और बीमारियों के बैक्टीरिया और वाइरस शरीर की प्रणाली पर हमला कर आसानी से उसे खराब करने लगते हैं। इसमें से कई आदतों के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने वाली आदतें

- लगातार देर तक धूप में रहने से इम्यून पावर कमजोर हो सकती है। यूं तो सुबह की ताजी सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है लेकिन बहुत ज्यादा तेज धूप में रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है और त्वचा कैंसर तक की समस्या हो सकती है।
- बहुत ज्यादा तनाव से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। तनाव होने पर शरीर में कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) का स्तर बढ़ जाता है जिससे इम्यूनिटी तो कमजोर होती ही है, साथ ही पाचन क्रिया भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है।
- साफ-सफाई के प्रति लचर व्यवहार भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नाकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। शरीर का साफ-सफाई पर ध्यान ना देने से हानिकारक कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे कई बीमारियों और इंफेक्शन हो जाते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा शराब का सेवन या धूम्रपान भी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है।
- जाने-अनजाने में ही सही लेकिन खाने की गलत आदतें और बदपरहेजी धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक त्क्षमता को खत्म करती हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकती हैं। एक ताजा शोध के अनुसार तो डिब्बाबंद और माइक्रोवेव में बनाए खाद्य को खाने से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद न लेने से ये दिमाग व पाचन क्रिया को सीधे-सीधे प्रभावित करती है। और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इसलिए समय से सोएं और पूरी नींद लें। नियमित एक्सरसाइज करें और अच्छा भोजन करें। इस तरह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे।



लैवेंडर तेल और बर्न्स - क्या फायदे हैं?

लैवेंडर तेल के उपयोग करने का मुख्य लाभ, प्राकृतिक रूप से त्वचा के जलने का उपचार है। हालांकि बाजार में कई तरह की बर्न क्रीम मिलती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर में हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य और भलाई की परवाह करते हैं तो आवश्यक तेल जैसे लैवेंडर त्वचा के जलने के उपचार के लिए एक बढ़िया घरेलू उपाय हो सकता है।



मोटापा कम करने के लिए मुद्राएं

मोटापा ऐसी समस्या है जो अपने साथ कई तरह की बीमारी लेकर आती है। समय रहते काबू पाना बहुत जरूरी है। मोटापा कम करने में योग बहुत कारगर होता है। योगासनों के जरिए आप आसानी से मोटापा कम कर सकते हैं। मोटापे को दूर करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। इनका अभ्यास नियमित रूप से कम से कम 15 से 45 मिनट तक करेंगे, तभी इनका फायदा मिलेगा।



खुशखबरी देने का सही समय है बारहवां हफ्ता

गर्भावस्था का बारहवां हफ्ता यानी गर्भवर्ती महिला दूसरी तिमाही में प्रवेश करने वाली है। अब गर्भपात का जोखिम न के बराबर है। यदि मां बनने वाली महिला दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खुशखबरी नहीं दी है तो अब उन्हें यह खबर दे सकती हैं। दूसरी तिमाही में प्रवेश करने पर महिलाएं राहत महसूस करती हैं। अब उन्हें जल्द ही मां बनने का अहसास मन ही मन खुशी देता है। इस समय कुछ महिलाओं का बेबी बंप दिखाई देने लगता है, जब्कि कुछ का दिखाई भी नहीं देता। यदि गर्भवर्ती महिला के अंदर कोई शारीरिक बदलाव नहीं हो रहा तो परेशानी होने की काई बात नहीं है। आंतरिक परिवर्तन लगातार जारी हैं।

बच्चे का विकास

दूसरी तिमाही में प्रवेश कर लिया है, अब बच्चे के विकास में तेजी आएगी। मस्तिष्क हार्मोन का उत्पादन शुरू करेगा और तंत्रिका कोशिकाएं भी जल्द बढ़ेंगी। गर्भ में पल रहा शिशु तरल पदार्थ को चूसना और आहार को निगलना शुरू कर देगा। सब कुछ सही रहने पर शिशु की लंबाई और आकार में परिवर्तन होता रहेगा।

बच्चे की मुठ्ठी, खोलने और बंद करने की प्रक्रिया भी अब शुरू होने लगती है। समय समय पर बच्चे के होठ और भौंहे सिकुड़ने लगते हैं। आंखें और कान चेहने के अनुपात में विकसित होने शुरू हो जाता हैं। हफ्तों और महीनों का समय बीतने के साथ शिशु की बनावट में और भी बदलाव आने लगता है।

शरीर में परिवर्तन

गर्भावस्था के बारहवें सप्ताह के दौरान बच्चे की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के कारण गर्भाश्य के आकार में भी परिवर्तन दिखाई देगा। अब मां का पेट पहले से बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वजन में दो से तीन पाउंड की वृद्धि हो जाएगी। त्वचा के रंग में भी कुछ परिवर्तन होगा। यदि त्वचा पर दाग हैं तो ये गर्भावस्था के दौरान और गहरे हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में पेट के केंद्र से एक गहरे रंग का रेशा दिखाई देना शुरू हो सकता है, यह शिशु के जन्म के बाद गायब भी हो सकता है।

हर महिला के गर्भावस्था के दौरान अलग-अलग लक्षण होते हैं, इसलिए यदि किसी महिला के लक्षण किसी से भिन्न हैं तो चिंता की बात नहीं है। गर्भावस्था के बारहवें सप्ताह में मां बनने वाली महिला के दिल में जलन भी अधिक हो सकती है। इसमें कमी लाने के लिए दिन भर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आहार लें। चिकित्सक से ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी करें, जिनके सेवन से दिल में जलन न हो। यह समय मोलर गर्भावस्था का हो सकता है। इस समय नाल ठीक से विकसित नहीं होती। धब्बे या योनि से खून बहता दिखाई दे सकता है। इस तरह की परेशानी होने पर बिना किसी लापरवाही के चिकित्सक से परामर्श करें। इस तरह की परेशानी गर्भपात का कारण भी बन सकती है।

क्या उम्मीद की जाती है

दूसरी तिमाही में जाने पर गर्भपात का जोखिम काफी कम हो गया है। सुबह को होने वाली परेशानी, थकान और मितली जैसी दिक्कतें भी कम होंगी। पहले से अच्छा महसूस कर रही होगी। आपके हार्मोन बच्चे के विकास के साथ समायोजन कर रहे हैं और सब अच्छी तरह से चल रहा होना चाहिए। त्वचा सूर्य के प्रकाश के प्रति अतिसंवेदनशील बनी महसूस हो सकती है। इस समय त्वचा पर दाग या काले धब्बे बन सकते हैं। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। संतुलित आहार योजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं रखें। जो महिलाएं पहले गर्भवती रह चुकी हैं, उनसे बात करें और उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करें। अपने और बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए समय-समय पर चिकित्सक से मिलते रहें।

सुझाव / सलाह

सफलता पूर्वक पहली तिमाही पूरी कर ली है। अब दूसरी तिमाही की शुरूआत हो चुकी है। पहले के मुकाबले शारीरिक व मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रही हैं। यदि आने वाले दिनों में गर्भवर्ती महिला को यात्रा करने का विचार बन रहा है तो उसके लिए यह समय बेहतर है। सुबह को होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वाली बधाईयां आपकी खुशी को दोगुना कर देंगी। अन्य महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान की बातों को सुनकर उनसे अपने अनुभवों की तुलना न करें। जरूरी नहीं कि हर महिला की गर्भावस्था के दौरान का अनुभव एक जैसा ही हो। यदि इस सबके बाद मन में अगर कोई प्रश्न है तो चिकित्सक से परामर्श करना अच्छा रहेगा।

गर्भावस्था के बारहवें हफ्ते में

- पहली तिमाही के मुकाबले गर्भवर्ती महिला को कम थकान और मितली भी कम आएगी। इस समय कोशिश करें कि तनाव न लें। इससे ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी।
- अब एरोबिक्स एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में लागू कर सकती हैं। इसके लिए यह सही समय है।
- अपनी दिनचर्या में हल्की एक्सरसाइज को शामिल करें, इससे मां और गर्भस्थ शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे।





कैंसर से लड़ने में मददगार हैं ये जादुई फूल

कैंसर रोग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। कैंसर के तेजी से बढ़ते मामले और जटिल इलाज के चलते लोगों के लिए यह रोग काफी डरावना बन चुका है। इसका बारे में बात करने से भी लोग घबराते हैं। शोध बताते हैं कि कैंसर दुनिया भर में हर साल हज़ारों मौतों का कारण बनता है। यह दरअसल शरीर में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि होती है, जो ऊतकों को मार देती हैं और अंततः शारीरिक प्रणाली को नष्ट कर देती हैं। कैंसर मानव प्रणाली के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कैंसर के सबसे आम प्रकार में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर व लिम्फोमा आदि शामिल होते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि कुछ प्राकृतिक औषधियों की मदद से भी कैंसर का इलाज किया जा सकता है। चलिए इस विषय के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि माना जाता है कि डेंडलाइन का फूल कैंसर के उपचार में मददगार होता है।

कैंसर का इलाज: हालांकि कैंसर के कई प्रकारों का इलाज करना संभव होता है, लेकिन इस बीमारी के दोबारा होने का भी बड़ा जोखिम रहता है, जिसके चलते ये बीमारी और भी घातक हो जाती है। इस रोग के साथ इलाज के स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य संगठनों और अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कैंसर के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के प्रयास में हर साल लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहे हैं। हालांकि कैंसर के इलाज के लिये दवाएं, कीमो थेरेपी तथा जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आदि कि मदद से कैंसर के उपचार और बचाव को प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैंसर के उपचार और रोकथाम के लिए प्राकृतिक नुस्खों की मदद भी ली जा सकती है। डेंडलाइन का फूल जिसे कामफूल के नाम से भी जाना जाता है, के फूल के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इसमें कैंसर से लड़ सकने वाले असाधारण औषधीय गुण होते हैं।



कैंसर से लड़ने की क्षमता: डेंडलाइन का फूल, खासतौर पर इसकी जड़ में असंख्य विटामिन और खनिज होते हैं, जोकि मानव प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। डेंडलाइन का फूल विटामिन डी, सी और बी, आयरन, सिलिकॉन, जिंक व पोटेशियम आदि पोषक तत्वों का शरीर में संचार करता है। इन सबके मनुष्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह फूल कोशिकाओं को पोषण देता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके साथ - साथ डेंडलाइन कब्ज, गुर्दे और यकृत रोग, पीलिया, वायरल फ्लू, आदि को भी दूर कर सकता है। यह फूल नई बनी मां के दूध का उत्पादन भी कुशलता से बढ़ा सकता है। डेंडलाइन के फूल को एक उत्कृष्ट रक्त शोधक भी माना जाता है, जो कि चयापचय दर को ठीक बनाए रखने और रक्त विकारों को रोकने में मदद करता है। इस सभी स्वास्थ्य लाभों के साथ डेंडलाइन में कैंसर से लजडने की काबिलियत बी होती है।

विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि डेंडलाइन की जड़ में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकने वाले गुण होते हैं।

जानें पोकवीड केब हर्ब्स के गुणों के बारे में

पोकवीड एक बारहमासी जड़ीबूटी है, जो पूर्वी उत्तर अमेरिका का मूल निवासी है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। इसके बेरीज् और सूखी जड़ों का इस्तेमाल हर्बल उपचार में किया जाता है। पोकवीड सप्लीमेंट अर्क, टिंचर, पाउडर और पुलटिस के रूप में उपलब्ध है। पोकवीड के लिए कोई मानक खुराक निश्चित नहीं हैं।



पोकवीड के गुण

पोक एंटीबायोटिक, एंटी-इंफ्लेमेंटरी, एंटी-रूमेटिक, एंटी-स्कर्वीजनक, एंटी-सिफिलिटिक और एंटी-ट्यूमर के रूप में कार्य करता है। इस संयंत्र के कुछ हिस्सों जैसे बेरीज् और जड़ों को हर्बल उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पोकवीड एक तीखी कड़वी जड़ी-बूटी है जो प्रतिरक्षा और लसीका प्रणालियों के कार्य में मददगार होती है।

बीमारियों के लिए पोकवीड

पोकवीड की जड़ का इस्तेमाल दर्दनाक मसल्स, जोड़ों (गठिया) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यह नाक, गला, और सीने में सूजन के अलावा टांसिलाइटिस, कर्कश गले, लसीका ग्रंथियों की सूजन, ब्रेस्ट में दर्द और सूजन किया जाता है। परंपरागत रूप से, हालांकि, पोकवीड जड़ का इस्तेमाल कभी कभार ही करना चाहिए। अमेरिका के मूल निवासी पोकवीड का चिकित्सा के रूप में इसकी जड़ का सबसे आम उपयोग उल्टी को प्रेरित करने के लिए रेचक के रूप में होता है। बेरीज् को भोजन में रंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और वास्तव में अभी भी खाद्य उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसे कच्चा खाया जाता है तो संयंत्र द्वारा उत्पादित एंजाइम जैसे लेक्टिंस लाल रक्त कोशिकाओं आपस में जुड़ जाती है। लेक्टिंस चिपकने वाले प्रोटीन हैं। ऐसे लेक्टिंस जो ब्लड टाइप के साथ मेल नहीं खाते, शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। भोजन से आने वाले कई लेक्टिंस हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत असर होता है। अगर ये लेक्टिंस ब्लड ग्रुप के साथ मेल नहीं खाता, तो शरीर में जलन, सूजन हो सकती है। पोकवीड को अवसादरोधी दवाओं, डिसुलफिरम, ओरल गर्भ निरोधकों और प्रजनन की दवाएं ले रहे लोगों को द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा किसी भी जड़ी बूटियों ककको लेने से पहले अपने चिकित्सक और फार्मासिस्ट बताओ।

महिलाओं के लिए पोकवीड

पोकवीड महिलाओं की कई विशिष्ट बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रिओसिस, पोकवीड के निर्धारित उपयोग के साथ हटाया जा सकता है। पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट और पेट में दर्द को भी इसके इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। पोकवीड की जड़ में थोड़ी सी मात्रा मे तेल मिलाकर पेट पर हल्के हाथों से रगड़ने से आराम मिलता है। वैकल्पिक रूप से टिंचर की कम खुराक इस्तेमाल की जानी चाहिए। इन्टर्स्टिशल सिस्टाइटिस एक और भड़काऊ बीमारी है जिसे इसी टिंचर से ठीक किया जा सकता है। बवासीर के दर्द को भी इसकी जड़ों के सत्व से ठीक किया जा सकता है।



पोकवीड को इस्तेमाल कैसे करें

परंपरागत रूप से, पोकवीड के लाल पत्तों को लाकर पानी में उबलकर, अच्छे से निचोड़कर निकाल लें। फिर एक बार और उबला लें। ऐसा कम से कम तीन बार करना चाहिए और हर बार पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। इन उबले हुए पत्तों का इस्तेमाल सलाद के रूप में या चाय के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, यंग शूट को शतावरी के विकल्प के रूप में भी खाया जा सकता है। बेरीज् से रेड जूस निकाल कर फिर इसे पकाया जाता है। इस जूस का इस्तेमाल पाइ बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अन्य जूस में जेली बनाने के लिए भी किया जाता है। पोकवीड के किसी भी हिस्से को कच्चा, असंसाधित नहीं खाया जा सकता है।

अर्थराइटिस

पुराने दिनों से, रूमेटाइड अर्थराइटिस से जुड़े दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए टिंचर उपयोगी है। वैकल्पिक रूप से एक या दो सूखी बेरी लेकर उसे पूरा ही खा लें। बहुत कम मात्रा में टिंचर का इस्तेमाल सिर दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूती

पोकवीड में प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित रोगों के इलाज की क्षमता भी होती है, क्योंकि इसमें एंटी एड्स दवा के गुण और क्षमता होती है। यह प्रचुर मात्रा में टी-कोशिकाओं पर परस्पर प्रभाव डाल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।

श्वसन संक्रमण का इलाज

पोकवीड के काढ़े का सामान्यत गले में दर्द और टांसिलाइटिस, ग्रसनीशोथ, अपच जैसे श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, यह ग्रंथियों की सूजन और पुराने संक्रमण के इलाज में भी कारगर है।

कैंसर का इलाज

जल्द ही पोकवीड ने कैंसर का इलाज करने की क्षमता हासिल कर लोक्रिप्रयता प्राप्त कर ली है, विशेष रूप से स्तन और गर्भाशय के कैंसर के लिए। शोधों से पता चला है कि कैंसर की प्राकृतिक चिकित्सा के लिए यह जड़ी-बूटी बहुत ही फायदेमंद है। पोक की जड़ एंटीटॉक्सिन थेरेपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कुछ प्रकार के ट्यूमर विकास में बाधा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

रेसिपी



बटर गार्लिक फ्राइड राइस

सामग्री

दो कप पके हुए चावल, लहसुन की 6 कलियां बारीक कटी हुई, आधा कप हरा लहसुन बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ी चम्मच फ्रेंच बींस बारीक कटी हुई, आधा कप पत्तागोभी बारीक कटी हुई, आधा कप फूलगोभी बारीक कटी हुई, एक गाजर छीलकर कद्दूकस कर लें, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, दो बड़े चम्मच मक्खन, स्वादानुसार नमक

विधि

गैस पर नॉन स्टिक पैन में मक्खन गर्म करें। इसमें लहसुन और प्याज डालकर मध्यम आंच पर एक मिनट तक फ्राई करें। अब पैन में फ्रेंच बींस, फूलगोभी, पत्तागोभी, गाजर और नमक डालकर मिक्स करें। अब पके चावल, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा पानी छिड़ककर इन्हें मिलाएं। अब हरा लहसुन डालकर इसे मिक्स करें। फिर पैन को ढक दें और धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं। गैस को बंद करे 2 मिनट बाद पैन का ढक्कन खोलकर चावल को अच्छी तरह चलाएं। तैयार है बटर गार्लिक फ्राइड राइस। इन्हें प्लेट में निकालकर गर्मागर्म सर्व करें।



चिल्ली पनीर

सामग्री

पनीर - 300 ग्राम, ग्रीन कैप्सीकम - 1 (कटी हुई), रैड कैप्सीकम - 1 (कटी हुई), कार्न फ्लोर - 3-4 स्पून, टमाटो सास - 1/4 कप, तेल- 3 -4 चम्मच, सिरका-2 छोटी चम्मच, सोया सास- 2 छोटी चम्मच, चिल्ली सास- 2 छोटी चम्मच, हरी मिर्च - 2-3 (छोटी काटी हुई), अदरक - 1 इंच टुकड़ा (कद्दूकस), नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर- 1/4 छोटी चम्मच, चिल्ली फ्लेक्स -1/4 छोटी चम्मच, अजीनो मोटो-2 पिंच, पोदीना के पत्ते- 12

विधि

पनीर क्यूब्स को एक बाउल में रखें, उसमें डालें नमक, अदरक-लसहुन पेस्ट, मैदा, 1 छोटा चम्मच टोमाटो चिल्ली सॉस और अच्छे से मिलाएं। हरे प्याज को मोटा-मोटा काटें। एक नॉन स्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। लाल मिर्चों के छोटे टुकड़े करके उनके बीज निकालें और पैन में डालें। फिर हरे प्याज डालकर भूने। पैन में शिमला मिर्चे डालें और अच्छी तरह मिलाएं। नमक डालकर कुछ देर पकाएं। 1 बड़ा चममच टोमाटो चिल्ली सॉस डालें और 2 मिनिट तक पकने दें फिर आंच बुझा दें। पनीर के क्यूब्स को पैन में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। गारमागरम परोसें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू

बेंगलुरु। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। खराब मौसम के कारण उनका विमान पहले जयपुर डायवर्ट किया गया था, जिसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत उनका इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। इसी बीच राज्य के प्रमुख नेता डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिससे कांग्रेस के भीतर नए नेतृत्व और सत्ता के बदलाव को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में सिद्धारमैया, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल की राहुल गांधी के साथ अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके साथ ही डीके शिवकुमार भी कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे, हालांकि उनकी बैठक का समय अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है।



1 या 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं डीके शिवकुमार

बेंगलुरु। कर्नाटक में लंबे समय से चली आ रही लीडरशिप की खींचतान पर आखिरकार विराम लग ही गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब डीके शिवकुमार राज्य के सीएम बनने जा रहे हैं। सूत्रों ने संकेत दिया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 1 जून या 3 जून को शपथ लेने की संभावना है। सिद्धारमैया ने अपने उपमुख्यमंत्री का समर्थन किया है ताकि वे उनके उत्तराधिकारी बन सकें, और उन्होंने सभी से उनका समर्थन करने का आग्रह किया है। इस्तीफ़ा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उनसे पद छोड़ने के लिए कहा था और उनके लिए राज्य का हित सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि उन्हें राज्यसभा की सीट की पेशकश की गई थी।



पटरी पर दौड़ने को तैयार देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

हैदराबाद। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे बोर्ड ने उत्तरी रेलवे के जींद-सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 10 डिब्बों की इस विशेष ट्रेन को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, 1200 किलोवॉट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणोदन प्रणाली से लैस यह ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस अनूठी पहल के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। चूंकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए दुनिया के गिने-चुने देशों में ही इसका परीक्षण या संचालन किया जा रहा है। देश में इस पर्यावरण-अनुकूल ट्रेन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।



सुको ने विनेश को एशियन गेम्स के ट्रायल में मिली अनुमति

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाफ को राहत देते हुए एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया था पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया(डब्ल्यूएफआई) उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गयी थी। इस मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में अब विनेश के गेम्स 2026 के ट्रायल्स में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि विनेश ने देश का सिर ऊंचा किया है। साथ ही कहा, अगर कोई और होता तो बात दूसरी होती। उसने देश को गर्व कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जिस तरह सुनवाई की, उस पर चिंता भी जताई पर उनके आदेश में हस्तपेक्ष से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई की।



मानसून 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा, कम बारिश का अनुमान

नई दिल्ली । देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढने के आसार नहीं हैं। केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मानसून आने का अनुमान जताया था। इस तरह पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जून-जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीटवेव चलने की संभावना है। आमतौर पर उस वक्त तापमान 30-35 डिग्री तक रहता है। इस बार 3 डिग्री ज्यादा टेंपरेचर रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। जो सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम है। 13 अप्रैल को 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था। 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है।

सिद्धारमैया ने बेटे यतींद्र के लिए मांगा डिप्टी सीएम पद, हाईकमान पर दबाव!

नईदिल्ली। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के बीच अपने बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया के लिए उपमुख्यमंत्री पद की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने दिल्ली में हुई कई बैठकों के दौरान कांग्रेस उच्च कमान को अपनी यह मांग बताई। पार्टी उनके इस्तीफे के बाद कर्नाटक में अगली सरकार के गठन को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है।



सूत्रों ने आगे बताया कि सिद्धारमैया ने नेतृत्व को सूचित किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.जे. जॉर्ज और जी. परमेश्वर ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों नेताओं को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये घटनाक्रम तब सामने आए जब सिद्धारमैया राजधानी में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे।

सिद्धारमैया के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम को सुचारू परिवर्तन बताया और कहा कि नेतृत्व में यह बदलाव सिद्धारमैया के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के समय से ही तय था। मोइली ने कहा कि सिद्धारमैया ने पार्टी और राज्य दोनों की प्रभावी ढंग से सेवा की है और विश्वास जताया कि नए नेतृत्व में कांग्रेस सरकार स्थिर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह एक परिवर्तन है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया और 8 वर्षों तक हमारे आधिकारिक नेता रहे। ढाई साल बाद नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के समय ही लिया गया था, लेकिन उन्हें कुछ और महीनों तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई। उन्हें पता था कि परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होगा।

उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से कांग्रेस सरकार अपने शेष कार्यकाल के लिए मजबूत होगी और शासन में निरंतरता सुनिश्चित होगी। मोइली ने कहा कि उन्होंने पार्टी और राज्य सरकार में अच्छा काम किया सरकार का परिवर्तन सुचारू रूप से हो रहा है, जिसका अर्थ है कि अगले 2 वर्षों तक एक मजबूत सरकार रहेगी और कांग्रेस की विरासत जारी रहेगीज मुझे नहीं लगता कि इस बदलाव का अचानक कोई प्रभाव पड़ेगा, वह कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।

अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच, मोइली ने कहा कि अब यह मामला पूरी तरह से कांग्रेस हाई कमांड के हाथ में है और उन्होंने विश्वास जताया कि नेतृत्व सर्वसम्मति से निर्णय लेगा। मोइली ने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चा और बहस समाप्त हो चुकी है और अब अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से काम करती आई है और सर्वसम्मति पर पहुंचने से पहले बहस और आंतरिक चर्चाओं के लिए जगह देती है।

वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुझे लगता है कि अब राय देने का समय समाप्त हो गया है। अब यह मामला नेताओं के उच्च स्तर पर है और वे पहले ही मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि वे मामलों को सुलझा लेंगे। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वे निर्णय लेने वाले हैं और वे अब उच्च स्तर पर बैठक कर रहे हैं। वे इसका समाधान निकाल लेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस में, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा से एक लोकतांत्रिक पार्टी रहे हैं और हम हमेशा अपनी चर्चाओं और बहसों के लिए गुंजाइश रखते हैं।

बंगाल में भाजपा की जीत के बाद आरएसएस से जुड़े संगठनों का बढ़ा दायरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव का असर अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में भी साफ दिखाई देने लगा है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के कुछ ही हफ्तों बाद आरएसएस से जुड़े छात्र और शिक्षक संगठनों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी सक्रियता तेजी से बढ़ा दी है। कभी वामपंथ और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाले कैंपस अब धीरे-धीरे नए वैचारिक बदलाव की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उत्तर बंगाल के कॉलेज कैंटीन से लेकर कोलकाता के विश्वविद्यालय परिसरों तक माहौल बदलता दिख रहा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), जो लंबे समय तक बंगाल की छात्र राजनीति में सीमित प्रभाव रखती थी, अब तेजी से विस्तार कर रही है। संगठन का दावा है कि चुनाव से पहले उसकी मौजूदगी करीब 96 कॉलेजों तक थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। एबीवीपी नेताओं के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्र संगठन से जुड़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नए यूनिट बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है।

एबीवीपी फिलहाल सीधे कैंपस कमेटियां घोषित करने के बजाय छात्रों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल नेटवर्क का सहारा ले रही है। संगठन पहले इच्छुक छात्रों की जांच और वैचारिक समझ को परख रहा है। सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में टीएमसी छात्र परिषद (टीएमसीपी और एसएफआई से जुड़े कई छात्र भी एबीवीपी के संपर्क में आए हैं। सिर्फ छात्र संगठन ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच भी आरआरएस समर्थित संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। भारतीय शिक्षण मंडल और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) का दावा है कि उनकी सदस्यता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। एबीआरएसएम के पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य के कई जिलों में अब शिक्षक और कर्मचारी बड़ी संख्या में संगठन से जुड़ना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ संगठनात्मक विस्तार नहीं बल्कि बंगाल की शिक्षा और छात्र राजनीति में बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। दशकों तक वामपंथी विचारधारा का गढ़ रहे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति की चर्चा बढ़ने लगी है। आरएसएस से जुड़े रणनीतिकार लंबे समय से मानते रहे हैं कि बंगाल में स्थायी राजनीतिक प्रभाव के लिए शिक्षा संस्थानों में मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है।

टीएमसी में बड़ी फूट, असम प्रमुख मजूमदार ने दिया इस्तीफा

कहा- पार्टी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए करती है काम

गुवाहाटी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के असम प्रमुख अभिजीत मजूमदार ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी असम और पश्चिम बंगाल दोनों में केवल मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में लगातार हो रहे इस्तीफों की कड़ी में उनका इस्तीफा भी जुड़ गया है। मजूमदार ने अपना इस्तीफा पत्र ममता बनर्जी को ईमेल के जरिए भेजा। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि असम में पार्टी की छवि तेजी से एक ऐसे संगठन की बन गई है जो केवल मुसलमानों के लिए काम करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भी यही रवैया दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों में आगे न बढ़ पाने की बात कहते हुए मजूमदार ने कहा कि पार्टी के कामकाज और राजनीतिक दिशा ने उनके लिए इससे जुड़े रहना असंभव बना दिया है।

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे और आंतरिक मतभेदों के चलते पार्टी में साफ तौर पर दिख रही अशांति के बीच उनका इस्तीफा आया है। कुछ सप्ताह पहले ही, टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने भ्रष्टाचार के आरोपों और आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले के निपटारे को कारण बताते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में सेन ने कहा कि वे पार्टी का बचाव करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने इसे अनैतिक कृत्य और भ्रष्टाचार से संबंधित विवाद बताया है। उन्होंने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामला, अभया मामला और कथित नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले जैसे मुद्दों का जिक्र किया। सेन ने यह भी कहा कि वे हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए पद छोड़ रहे हैं। सेन ने लिखा कि भले ही मैं कई मुश्किल दौर में उनके विचारों से सहमत नहीं था, फिर भी मैंने कई विवादास्पद मुद्दों पर मीडिया में पार्टी के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाई। लेकिन मौजूदा हालात में, जब बंगाल की जनता ने हमें कई अनैतिक कृत्यों और भ्रष्टाचार के कारण नकार दिया है, तो मेरा मन अब प्रवक्ता के रूप में उनका समर्थन करने को तैयार नहीं है।



टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी पार्टी की महिला विंग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और कई संगठनात्मक पदों से भी हट गईं। अपने पत्र में दस्तीदार ने आरोप लगाया कि पार्टी उन्हें एक साथी सांसद द्वारा कथित दुर्व्यवहार और मौखिक गाली-गलौज से बचाने में विफल रही, जिसका स्पष्ट संकेत वरिष्ठ टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी से था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद इन इस्तीफों ने पार्टी के भीतर गहरी दरारें उजागर कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 मई को घोषित 293 सीटों में से रिकॉर्ड 207 सीटें जीतकर राज्य में टीएमसी के लंबे शासन का अंत कर दिया। इसके बाद भाजपा ने 21 मई को हुए पुनर्मतमत चुनाव में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करके अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया, क्योंकि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

पीवी सिंधु को एन से यंग ने क्वार्टरफाइनल में हराया

सिंगापुर। अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का सिंगापुर ओपन सुपर 750 में सफर क्वार्टरफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एन से यंग के खिलाफ कड़े मुकाबले में हार के साथ समाप्त हो गया। हालांकि स्कोर 17-21, 14-21 रहा और मैच 48 मिनट में खत्म हुआ, लेकिन यह देखने में जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी था। इस मैच में सिंधु की आक्रामक खेल शैली और महिला बैडमिंटन के शीर्ष स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई दीं।



सिंधु ने आक्रामक शुरुआत की और अपने शक्तिशाली ओवरहेड शॉट्स और तेज स्मैश से एन से यंग को शुरुआत में ही परेशान कर दिया। उन्होंने 22 और 31 शॉट्स की दो लंबी रैलियां भी सटीक विनर्स के साथ जीतीं, जिससे शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी, जो अपनी असाधारण रक्षात्मक शैली और गति के लिए जानी जाती हैं, कुछ समय के लिए विचलित हो गईं। एक समय सिंधु ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया और बाद में पहले गेम में कोरियाई खिलाड़ी को कड़ी टक्कर देते हुए अंतर को 14-13 तक कम कर दिया।

हालांकि, नेट पर और फ्रंट कोर्ट में बार-बार हुई गलतियों ने सिंधु की लय को तोड़ दिया। शानदार वापसी करते हुए और 19-17 पर 40 शॉट की मैराथन रैली जीतने के बावजूद, सिंधु ने अंतत: पहला गेम गंवा दिया जब उनका शॉट लंबा चला गया, जिससे एन ने गेम अपने नाम कर लिया। भारतीय शटलर सिंधु के लिए दूसरा गेम मुश्किल से शुरू हुआ, क्योंकि एन ने 6-0 की बढ़त बना ली। सिंधु ने कुछ हद तक वापसी की और अंतर को 7-9 तक कम कर दिया, लेकिन कोरियाई खिलाड़ी ने मध्यांतर तक अपना दबदबा बनाए रखा। एक विवादित नेट कॉल के बाद कुछ देर के लिए तनाव भी पैदा हुआ, हालांकि इससे खेल की गति पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1092 अंक टूटा निफ्टी 23,548 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों की धारणा कमजोर रही, जिसका सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी50 पर पड़ा। सेंसेक्स 1,092.06 अंक यानी 1.44 प्रतिशत गिरकर 74,775.74 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी50 में भी 359.4 अंक यानी 1.50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 23,547.75 पर बंद हुआ। 30-सेंसेक्स कंपनियों में से टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएंडटी, एशियन पेंट्स और इंफोसिस के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। बाजार की कमजोरी केवल लार्जकैप तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापक बाजार पर भी दबाव देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.33 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।

प्लास्टिक नोटों की ओर आरबीआई का कदम

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पिछले कुछ वर्षों में करेंसी नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पॉलिमर नोट लाने पर फिर से विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर केंद्रीय बैंक की पटना और मुंबई में हुई पिछली दो बोर्ड बैठकों में चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लास्टिक के नोट बनाने में खर्च कम आएगा और वे लंबे समय तक चलेंगे। प्लास्टिक नोटों के सार्वजनिक प्रयोग का परीक्षण शुरू करने की घोषणा जल्द हो सकती है। घटनाक्रम से अवगत सूत्र ने बताया, 'उत्पादन लागत में स्पष्ट लाभ है। साथ ही एटीएम पॉलिमर आधारित नोट भी निकाल सकेंगे। हमारे पास अब इसके लिए आवश्यक संसाधन मौजूद हैं।' आरबीआई ने कहा था कि 2024-25 के दौरान नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है और मजबूत वृहद आर्थिक आधार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि को सहारा देंगे। आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट के अनुसार, ऊंची ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति शृंखला में बाधाओं और वैश्विक बाजारों से आने वाली चुनौतियों के बावजूद कंपनियों एवं बैंकिंग क्षेत्र के मजबूत बही-खाते तथा सरकार का पूंजीगत व्यय पर जोर भारत की मजबूत वृद्धि गति के लिए अनुकूल है। इसमें कहा गया है कि 2026 में भू-राजनीतिक जोखिम वैश्विक वृद्धि के लिए प्रमुख बाधा बनकर उभरा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने का असर वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, मध्यम वैश्विक वृद्धि के परिदृश्य के बीच 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

बिगड़ा रसोई का बजट, 13% बढ़ गईं खाद्य तेल की कीमतें

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल का असर अब सीधे भारतीय घरों की रसोई तक पहुंच गया है। फरवरी से अब तक खाद्य तेलों की थोक कीमतों में करीब 13 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट बिगड़ने लगा है। पेट्रोल-डीजल की महंगाई के बीच खाद्य तेलों की यह नई मार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चिंता बन गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिम एशिया युद्ध के कारण ट्रांसपोर्टेशन, बीमा और शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से पाम तेल आयात महंगा पड़ रहा है। बाजार जानकारों का कहना है कि फिलहाल कीमतों में हल्की मुनाफावसूली दिख सकती है लेकिन लंबी अवधि में खाद्य तेलों के दाम ऊंचे बने रहने की आशंका है।

अमेरिका-ईरान युद्ध से महंगाई के कारण आमजन प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

भले ही 1970 के तेल संकट जैसे हालात होने की संभावना ना हो या 2008 जैसी वित्तीय मंदी के हालात ना हो फिर भी एक बात साफ है कि अमेरिका-ईरान के बीच करीब तीन माह से चल रहे युद्ध के नकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। चाहे एशिया के देश हो या फिर योरोपीय देश सभी केवल वैश्विक तनाव ही नहीं अपितु ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने से बढ़ते दामों को रोकने में विफल ही हो रहे हैं। पिछले दस-पन्द्रह दिनों में ही हमारे देश में पेट्रोल- एलपीजी- सीएनजी- पीएनजी के दामों में एक बार नहीं अपितु तीन बार बढ़ोतरी हो चुकी है। हांलाकि वर्तमान हालातों में सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्ष चाहे लाख आरोप लगाये या आंदोलन-प्रदर्शन करें पर अंतरराष्ट्रीय हालातों से आंख नहीं मूंदनी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमजन से आग्रह को भी इसी संदर्भ में सकारात्मकता से लिया जाना चाहिए। वैसे भी जब संकट का दौर हो और उस संकट के लिए हम या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं हो तो फिर देश में नकारात्मक माहौल बनाने के स्थान पर सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का नहीं अपितु सभी राजनीतिक दलों का दायित्व हो जाता है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ईंधन संकट का बड़ा कारण अमेरिका-ईरान युद्ध ना होकर अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण हार्मुज संकट बन गया है। हार्मुज के रास्ते से ही कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और तनाव के चलते हार्मुज जनडमरुमध्य रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है इससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यह तो वैकल्पिक उर्जा के रुप में देश में सोलर, विण्ड एनर्जी के क्षेत्र में पिछले सालों



में योजनाबद्ध तरीके से तेजी से और बेहतर काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री इलेक्ट्रोनिक वाहनों के उपयोग या सोलर एनर्जी के उपयोग पर खुले तौर पर आग्रह करने की स्थिति में है। नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में देश में तेजी से काम हुआ है और हो रहा है जो एक हद तक संकट को कम करने में सहायक बन रहा है।

आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लोजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाएं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है। सीधी सी बात है जब आवागमन महंगा होगा चाहे वह आम आदमी, सार्वजनिक क्षेत्र या लोजिस्टिक का हो तो उसका सीधा सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा ही। यही कारण है ईंधन यानी तेल के भावों में बढ़ोतरी के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। इसके साथ ही आयात पर निर्भर वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक तेल का प्रष्न है देश में खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भी आयात पर निर्भरता अधिक है। लाख प्रयासों के बावजूद तिलहन मिशन से तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ा है पर अभी विदेशी निर्भरता बनी हुई ही है। इसी तरह से अन्य वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक सेवा क्षेत्र का प्रष्न है स्वीगी-जोमेटो आदि सेवा प्रदाताओं ने पिछले दिनों में अपने दामों में 16 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्लानों को रिवाइज किया हैं तो उबेर-ओला जैसे सेवा प्रदाताओं ने किराया बढ़ा दिया है। हो तो यहां तक रहा हैं कि बैंकों द्वारा जमाओं पर ब्याज दर में कमी लाना शुरु कर दिया है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोजिस्टिक लागत बढ़ेगी तो उसका असर सभी वस्तुओं में देखने को मिलेगा। भारत सरकार वेनेजुएला से वैकल्पिक तरीके से कच्चे तेल लाने का प्रयास कर रही है तो अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। पर यह साफ हो जाना चाहिए कि कच्चे तेल की आपूर्ति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह से संकट समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती।

जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पितः मुख्यमंत्री साय

'पद्मश्री डॉ. सुनीता गोडबोले एवं डॉ. रामचंद्र गोडबोले द्वारा बस्तर में किए गए सेवा कार्यों की मुख्यमंत्री ने की सराहना'

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी दंपति डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले से आत्मीय मुलाकात कर उनके द्वारा बस्तर और जनजातीय समाज के बीच चार दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। मुलाकात के दौरान गोडबोले दंपति ने मुख्यमंत्री को बताया कि बस्तर और बस्तरवासियों से हमें गहरा प्रेम है। हम गोंडी और हल्बी में उनसे संवाद करते हैं, यही हमारी संस्कृति है और अब हम बस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस आत्मीय भावना को बस्तर, उसकी संस्कृति और जनजातीय समाज के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केवल सेवा का विषय नहीं, बल्कि मानवीय आत्मीयता, संवेदनशीलता और सामाजिक



प्रतिबद्धता की दुर्लभ मिसाल है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका पद्मश्री सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश, विशेष रूप से बस्तर, जनजातीय समाज और बस्तरवासियों के सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल बने गोडबोले दंपति का सम्मानित होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले ने चार दशकों से अधिक समय तक बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सेवा का वास्तविक अर्थ समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अपनत्व, विश्वास और मानवीय संवेदना पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति ने जनजातीय समाज तक पहुंचकर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया, कुपोषण, टीबी, मलेरिया, पीलिया और अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलायी तथा शिक्षा और नशामुक्ति जैसे विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जनजातीय समाज के बीच बने रहना और सेवा करते रहना असाधारण समर्पण का उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति केवल चिकित्सक के रूप में नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मीय सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कठिन दौर में भी गोडबोले दंपति ने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा और मानवता को सर्वोपरि रखते हुए जनजातीय समाज के बीच लगातार कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि जब भय और असुरक्षा का वातावरण था, तब भी इनका बस्तर और उसके लोगों के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई।

छत्तीसगढ़ में मैंगों टूरिज्म की है अपार संभावनाएं : रमेन डेका

■ राष्ट्रीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया राज्यपाल श्री डेका ने



रायपुर। आम केवल एक फल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आम उत्पादों को बडे रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की।राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व में आम उत्पादन में अग्रणी है और देश में एक हजार से अधिक किस्मों के आम पाए जाते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थानीय आमों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के उत्पादन से अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां और महोत्सव देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों को एक-दूसरे की उन्नत खेती पद्धतियों, नई किस्मों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में आम उत्पादन की बहुत संभावनाएं है। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए भी इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के व्यापक अवसर मौजूद है।

मैंगों टूरिज्म की भी छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं है।राज्यपाल ने कहा कि आम उत्पादन के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को मिलकर कार्य करना चाहिए। डेका ने कहा कि हमारे जीवन को ईको फैंडली बनाना आज की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी



रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने के लिए प्रदेश स्तर पर एक बड़ी कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज जांजगीर-चांपा जिले के अग्रणी शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक महत्वपूर्ण संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती रीता यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्राचार्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि बैठक में किसी भी प्रतिनिधि को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कमान प्राचार्यों को खुद संभालनी होगी। बैठक में शामिल हुए 63 कॉलेजों के प्रमुख इस व्यापक रणनीतिक बैठक में बिलासपुर संभाग, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिले के शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

बैठक में शामिल संस्थानों में स्वशासी कॉलेज बिलासपुर संभाग के 2 शासकीय और 2 अशासकीय स्वशासी महाविद्यालय। जांजगीर-चांपा जिला के 11 शासकीय और 27 अशासकीय महाविद्यालय। सक्ती जिला के 8 शासकीय और 13 अशासकीय महाविद्यालय। इनके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर संभाग के आला अधिकारी भी इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का हिस्सा बने।

आयुक्त रीता यादव ने आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर महाविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से 5 एजेंडों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके अनुरूप पाठ्यक्रम व संसाधनों को ढालने के निर्देश दिए गए। सत्र 2026-27 के लिए कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने और विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने हेतु कड़े कदम उठाने को कहा गया।

रेलवे कॉलोनियों में क्लीन एयर ग्रीन स्पेस जागरूकता अभियान चलाया

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान-2026 (15 मई से 5 जून 2026) के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 27 से 30 मई 2026 तक मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर व्यापक जन-जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ भविष्य उन्मुख रेल परिचालन की दिशा में रेलवे के सतत प्रयास किए जा रहे हैं अपने आसपास हरियाली बढ़ाने आउटडोर एक्टिविटी करने। साथ ही यात्रियों एवं कर्मचारियों को एकल-उपयोग प्लास्टिक के प्रयोग से बचने, प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित निपटान तथा स्टेशन परिसरों को स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाए रखने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा हैं। क्लीन एयर ग्रीन स्पेस जागरूकता अभियान के अंतर्गत डब्ल्यूआरएस एवं खारून रेल विहार रेलवे कॉलोनी में जनजागरूकता अभियान चलाया गया। र



नागरिकों की डेटा सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मयंक अग्रवाल

राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला संपन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं में विश्वसनीयता और डेटा गवर्नेंस को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (ष्ट।द्बक्क्र) एवं भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (ह्दद्मत्रष्ठ) के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न शासकीय विभागों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी अनुपालन को लेकर कड़े व स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।



कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल ने राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना शासन की मुख्य प्राथमिकता है।

डीपीडीपी अधिनियम केवल एक विधिक या कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह शासन व्यवस्था में डिजाइन में ही गोपनीयता एवं नागरिक-केंद्रित डेटा गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अग्रवाल ने राज्य की तकनीकी प्रगति साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेवा सेतु प्लेटफॉर्म का डिजिलॉकर, उमंग और माय स्कीम जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकरण किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

हसदेव में अडानी के लिए फिर पेड़ काटे जायेंगे : दीपक बैज

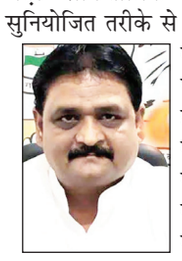
रायपुर। भाजपा सरकार पर छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने पर तुली हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार के अडानी परस्त नीतियों से हसदेव अरण्य के घने जंगलों पर संकट उत्पन्न हो गया है। मोदी के मित्र अडानी के मुनाफे के लिए सरगुजा रेंज के केते एक्सटेंशन के खुदाई का गौतम अडानी को देने के लिए इस सरकार ने अनुमति दी है। अब रामगढ़ की पहाड़ियां, प्राचीन नाट्यशाला, सीता गुफा, जानकी रसोई, प्रभु श्री राम



के वन गमन पथ की पुण्य स्मृतियों को अडानी के आर्थिक लाभ के लिए संकट में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइनिंग और पिट हेड कोल वॉशरी परियोजना के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उपयोग में बदलने की सिफारिश कर दी है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा गया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही 7 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई का रास्ता साफ हो जाएगा। यह वही इलाका है जिसे सेंट्रल इंडिया का लंग्स ज़ोन कहा जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हसदेव अरण्य का यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची का भाग है, जहां नए खदान स्थापित करने का लगातार विरोध स्थानीय आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार टेस्ट परीक्षा नहीं करवा पा रहीः शुक्ला

रायपुर। पेपर लीक होने के बाद अब नीट की परीक्षा की सुरक्षा के लिए वायुसेना लगाये जाने का मोदी सरकार का निर्णय बताता है कि मोदी सरकार से देश की व्यवस्थायें संभल नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह मोदी सरकार की बेचारगी को दर्शाता है। 140 करोड़ देश की, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार एक टेस्ट परीक्षा सुनियोजित तरीके से नहीं करवा सकती है। कांग्रेस



की सरकारों में 7 दशक से यूपीएससी की परीक्षा ईमानदारी और पारदर्शिता से कराने वाली, भारत की केंद्र सरकार एक टेस्ट परीक्षा नहीं करवा पा रही। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी परीक्षा की जवाबदेही वायुसेना को सौपी जा रही है। पिछले दो बार से नीट की परीक्षा की गोपनीयता को बरकरार नहीं रख पाने वाली मोदी सरकार ने मान लिया है कि उसमें देश की आंतरिक व्यवस्था भी संभालने की क्षमता नहीं बची है। इसीलिए वह टेस्ट परीक्षा में वायु सेना की मदद लेने जा रही है। अपनी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की ईमानदारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नीट के परीक्षा के प्रश्न पत्र रक्षा प्रतिष्ठानों में रखने की योजना है तथा उसे वायुसेना के माध्यम से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जायेगा।

पेट्रोल-डीजल में सेस हटाकर राहत दे सरकारः धनंजय सिंह

रायपुर। पेट्रोल-डीजल में वैट टैक्स 50 प्रतिशत तक कटौती एवं सेस को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा पेट्रोल-डीजल की बढ़ते दामों ने महंगाई को तेज किया है जिससे हर वर्ग परेशान है। इस वक्त सरकार को पेट्रोल में 27 प्रतिशत एवं डीजल में 25 प्रतिशत लगने वाले वैट में 50 प्रतिशत तक कमी करना चाहिये, इसके अलावा सेस को खत्म करना चाहिये। वर्तमान में



पेट्रोल में 22 रु. एवं डीजल में 20 रु. प्रति लीटर टैक्स जनता से वसूला जा रहा है। डीजल की महंगाई के चलते ट्रांसपोर्ट भाड़ा, यात्री किराया बढ़ाने की मांग हो रही है। ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी। तेल, नमक, शक्कर, खाद, दवाई, टायर ट्यूब, सब्जी-भाजी, दाल, चांवल, दूध सहित सभी अतिआवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि होगी। खेती में लागत मूल्य बढ़ेगा। रोजमर्रा के कामो में असर पड़ेगा। जिसका सीधा असर गरीब तबका रोज कमाने खाने वाले मध्यवर्ग पर पड़ेगा। सरकार को इस विपरीत समय में जनता को राहत देने वैट टैक्स में तत्काल कटौती करना चाहिए। डीजल संकट एवं महंगाई के चलते ट्रांसपोर्ट, यात्री परिवहन सेवा, खेती-किसानी, उद्योग, होटल, व्यवसायी सभी परेशान है।

सत्ता के मद में भाजपाई अराजक हो गयेः वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मंदिरहसौद में पानी मांगने पर भाजपा पार्षद ने हत्या कर दिया। प्रदेश में पेयजल की समस्या कितनी ज्यादा गंभीर हो गयी है कि इसका भयावह एक उदाहरण राजधानी से लगे मंदिर हसौद में हुआ। जहाँ पर पानी नहीं पहुंचने की शिकायत भाजपा पार्षद को इतनी नागवार गुजरी उसने फरियादी नागरिक की हत्या कर लाश रेत में दफन कर दिया। जनता के द्वारा पानी मांगना



गुनाह हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मंदिरहसौद की हत्या भाजपाइयों के सत्ता के अहंकार का एक और उदाहरण है। एक दिन पहले भाजपा के सीतापुर विधायक ने एसडीएम और पुलिस की मौजदूगी में तहसीलदार की पिटाई किया। भाजपाई, मंत्री, विधायक, सांसद सुशासन त्यौहार में अधिकारियों को धमका-चमका रहे थे, अब वे मारपीट, हत्या में उत्तर आये है। एक तो आम जनता की समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे, ऊपर से फरियाद करने पर हत्या कर दे रहे है। सरकार की अकर्मण्यता के चलते ही स्थानीय निकाय मूलभूत सुविधा नही दे पा रहे है, फंड रोक दिये गये है, हाल ही में बस्तर के अंतागढ़ ब्लाक के सभी सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दिया।

अपराध थम नहीं रहा, सरकार बेफिक्र बनी हुई : वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि एक तरफ सरकार सुशासन तिहार मना रही है, दूसरी तरफ राजधानी सहित पूरे प्रदेश में हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है। राजधानी से लेकर दुर्ग और गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा तक चाकूबाजी और हत्या इस सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा के कुशासन में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है



और राजधानी रायपुर क्राइम कैपिटल। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, चाकूबाजी और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी हिंसक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और खुलेआम हो रही आपराधिक वारदातों, गैंगवार और दहशतगर्दी के कारण आम जनता में भय का माहौल है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार की अकर्मण्यता से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम सोशल मीडिया पर दहशत फैलाया जा रहा है। बदमाशों और अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए रील बनाकर खुलेआम धमकियां देने का नया ट्रेंड चल पड़ा है, जिस पर पुलिस नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम है।

उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना बनी वरदान

रायपुर। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 कबीरधाम जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों एवं किसानों को राहत देने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के लगभग 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार (सरचार्ज) में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अब तक 31392 निष्क्रिय उपभोक्ता सफलतापूर्वक लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही योजना के दायरे में आने वाले कुल 19188 पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं



में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। राजनांदगांव रीजन के अंतर्गत चारों जिलों के 07 विद्युत संभागों में सर्वाधिक पंडरिया संभाग से 17739, कवर्धा संभाग से 15325, मोहला संभाग से 2784, राजनांदगांव संभाग से 4775, खैरागढ़ संभाग से 3488, डोंगरगढ़ संभाग से 5182 एवं डोंगरगांव संभाग से 1207 सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुकें हैं। इन सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं अधिभार में 15 करोड़ 22 हजार रुपए की राशि का छूट प्रदान किया जा चुका है। लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 03 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीश सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए संभाग के 66 वितरण केंद्रों एवं 03 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमें न केवल केंद्रों पर मौजूद हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता और छूट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक कर रही हैं। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाना है। कार्यपालक निदेशक सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें।

सेवा सेतुः जनता के द्वार डिजिटल सरकार

■ लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन, अब 'सेवा सेतु केंद्र' के रूप में मिलेंगी 442 डिजिटल सेवाएं

रायपुर। 'जनता के द्वार डिजिटल सरकार' का अर्थ है सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और आम जनता तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करने की एक व्यापक पहल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में बीजापुर जिले में लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें अब 'सेवा सेतु केंद्र' के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

'सेवा सेतु' व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनी हैं। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अब लोक सेवा केंद्र 'सेवा सेतु केंद्र' और उनके ऑपरेटर 'सेवा सेतु प्रबंधक' कहलाएंगे। जिले के सभी विकासखंडों के सचिवों को इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

पहले लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि अब सेवा सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं नागरिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए अब लोग अपने स्मार्टफोन से ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, और बिजली बिल भुगतान जैसी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन की स्थिति देखना और निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्राप्त करना संभव हो गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.